लखनऊ
मंगलवार 13 जनवरी, 2026
वर्ष : 11 | अंकः 144
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8
UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार न दें।

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi

NIGHT 10° Low

संक्षेप

मुंबई विवाद पर आदित्य ठाकरे का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा- पूरा महाराष्ट्र उद्योगपतियों को बेच रहे हैं

मुंबई। मुंबई को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अन्नामलाई के बयान पर विवाद खड़ा होने के एक दिन बाद, शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी का एकमात्र उद्देश्य राज्य का अपमान करना और उसे लूटना है। ठाकरे ने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि अन्नामलाई भाजपा का चेहरा हैं, जो शून्य है। वे वहां चुनाव नहीं जीत सके और अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। ऐसा दिखाया गया कि अगला प्रधानमंत्री वही होंगे, लेकिन वास्तव में, तमिलनाडु ने उन्हें शून्य साबित कर दिया है। जहां मुख्यमंत्री स्टालिन तमिलनाडु को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं ये लोग सिर्फ लड़ रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं। अन्नामलाई ने महाराष्ट्र का अपमान किया है, और राज्य इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अन्नामलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। ठाकरे का यह बयान भाजपा नेता अन्नामलाई के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने आगामी बीएमसी चुनावों से पहले मुंबई के धारावी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मुंबई 'एक अंतरराष्ट्रीय शहर है, महाराष्ट्र का शहर नहीं। यूबीटी नेता ने दावा किया कि भाजपा लगातार लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं या सांप्रदायिक मुद्दों में उलझाए रखने की कोशिश कर रही है, जबकि पूरे राज्य को उद्योगपतियों को बेच रही है। उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार चाहे जो भी करे, जनता जानती है कि सरकार को मुंबई या महाराष्ट्र से कोई लगाव नहीं है। लोग देखते हैं कि वे हमें लड़की बहन या हिंदू-मुस्लिम मुद्दों में कैसे उलझाए रखते हैं, जबकि पूरा महाराष्ट्र उद्योगपतियों को मुफ्त में दिया जा रहा है। यह शासन नहीं, कुशासन है।

ओवैसी हमारे देश की कौमी एकता में बहुत बड़ी बाधा हैं : मनोज तिवारी

नागपुर। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की कौमी एकता में ओवैसी जैसे लोग बहुत बड़ी बाधा हैं। नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वे सपने देखते हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। यह वही सोच है। आप हिजाब पहनने वाली महिलाओं की बात करते हैं, तो क्या आपकी कम्युनिटी में कोई और महिलाएं नहीं हैं जिनके बारे में आप बात कर सकें? यही समस्या है। अगर मुस्लिम किसी का समर्थन करेंगे, तो शरजील इमाम का करेंगे। हम तो अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा-महायुति गठबंधन ने लोगों का भरोसा जीता है, और कॉर्पोरेशन में भी जनता हमें जीताकर भेजेगी। लोगों के मन में यह साफ हो गया है कि अगर बिना किसी भेदभाव के कोई लोगों का भला चाहने वाला है तो वह भाजपा है। हमें पूरा भरोसा है कि नागपुर में हमारे सभी भाई-बहन और वोटर कॉर्पोरेशन में भाजपा को ही वोट देंगे। बीएमसी चुनाव और मेयर को लेकर हो रही बयानबाजी पर मनोज तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र में मेयर छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी होंगे।

यूपी में अब कर्फ्यू, दंगा नहीं, सब जगह चंगा, एआई हेल्थ समिट में बोले सीएम योगी, यहां सब खुशहाल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और आईटी विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय एआई हेल्थ समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं है। न ही दंगे होते हैं। अब यूपी में सब चंगा है। यहां हर कोई खुशहाल है। प्रदेश में निवेश भी आ रहा है। टूरिज्म भी बढ़ रहा है। यहां हर व्यक्ति अपने काम में लगा है। कारोबार में जुटा है, फिर चिंता क्यों हो? यह एक प्रयास है। सरकार के इसमें सहभागी बनने से प्रदेश की तरक्की सुनिश्चित हो रही है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें देश-विदेश से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग लेने आए थे। प्रदेश में जहां लाखों में लोग नहीं आते थे। उस प्रदेश के टूरिज्म, धार्मिक स्थलों पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। यह भी नए रोजगार का सृजन कर रहा है। कोई गाइड के रूप में, कोई टैक्सी चालक के रूप में तो कोई रेस्टोरेंट-होटल चलाकर इनसे कमाई कर रहा है। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा।

एआई पर दिया जोर

कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बीमारियों के पैटर्न और पूर्वानुमान की पहचान संभव होगी, जिससे किसी भी महामारी को फैलने से पहले ही रोका जा सकेगा। उन्होंने इसे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गेम चेंजर करार दिया। सीएम ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने तकनीक के बेहतर उपयोग से हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीएम योगी ने भरोसा जताया कि अब एआई के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा। एआई आधारित डेटा एनालिसिस से बीमारियों का ट्रेंड समझना आसान होगा और संवेदनशील इलाकों तक समय रहते पहुंचकर इलाज किया जा सकेगा।

इन्सेफलाइटिस का उदाहरण

सीएम योगी ने पूर्वांचल में इन्सेफलाइटिस पर काबू पाने का उदाहरण देते हुए कहा कि सघन सर्विलांस और डेटा आधारित रणनीति से आज उन क्षेत्रों में एक भी बच्चे की जान नहीं जा रही, जबकि पहले हर साल हजारों बच्चे बीमार पड़ते थे। उन्होंने कहा कि अब एआई इस प्रक्रिया को और प्रभावी बना देगा। सीएम ने ऐलान किया कि प्रदेश में सात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर इकोसिस्टम खड़ा किया जाएगा। एआई मिशन पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी अब दुनिया को तकनीक आधारित विकास मॉडल देने की स्थिति में पहुंच रहा है।

हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का जिक्र

सीएम योगी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि टेलीमेडिसिन सिस्टम में बड़ा सुधार हुआ है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। प्रदेश में अब 81 मेडिकल कॉलेज और दो एम्स संचालित हो रहे हैं। कोविड काल में वर्चुअल आईसीयू की शुरुआत कर सभी 75 जिलों में आईसीयू बेड बढ़ाए गए, जिससे यूपी का स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंचा है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क का निर्माण युद्धस्तर पर हो रहा है। एसजीपीजीआई लखनऊ में मेडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और गौतम बुद्ध नगर में एआई एंड इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी काम तेजी से चल रहा है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, 17 लापरवाह चिकित्साधिकारी बर्खास्त...जानें पूरा मामला

लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकारी अस्पतालों में लापरवाही बरतने वाले चिकित्साधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 17 चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये डॉक्टर लंबे समय से ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित पाए गए थे। मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले चार चिकित्साधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं, स्थानांतरण के बाद नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले डॉ. गजेंद्र सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। बीकेटी ट्रामा सेंटर के चार चिकित्साधिकारियों से कार्य में लापरवाही के आरोप में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके अलावा, तीन चिकित्साधिकारियों को लापरवाही पर चेतावनी जारी की गई है।

आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा, पीएम मोदी का ऐलान- जर्मनी- भारत मिलकर इससे लड़ेंगे

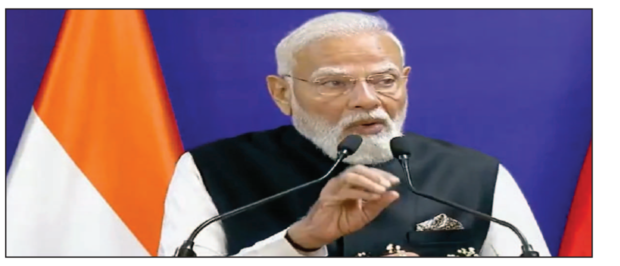

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की उपस्थिति में भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एकमत हैं कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। आज हमने यूक्रेन और गाज़ा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज़ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप पर भी काम करेंगे, जिससे सह-विकास और सह-उत्पादन के नए अवसर खुलेंगे। भारत और जर्मनी के बीच तकनीकी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान हैं। चांसलर मर्ज़ की ये यात्रा एक विशेष समय पर हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं।

चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा देने वाली धारा को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईसीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट देने वाली धारा को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह धारा चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक दायित्व निभाते समय किए गए कार्यों के लिए आजीवन कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई है। इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए

गए कार्यों के लिए संरक्षण दिया गया है। इन कार्यों को लेकर उनके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती।

याचिकाकर्ता की दलील

इस मामले में याचिका एनजीओ लोक प्रहरी ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून की नजर में समानता के अधिकार का हनन करती है। अगर चुनाव आयुक्त कोई गलती करे, तो भी इस धारा के चलते उन्हें कानूनी रूप से जवाबदेह ठहरा पाना असंभव है।

कोर्ट में क्या हुआ?

सोमवार, 12 जनवरी को मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच में लगा। एनजीओ की तरफ से उसके सचिव एस एन शुक्ला (पूर्व आईएएस) खुद पेश हुए। शुक्ला ने कहा कि CEC और EC को दी गई सुरक्षा सिर्फ कार्यकाल के दौरान ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी लागू होती है। ऐसी छूट राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों को भी प्राप्त नहीं है।

संवैधानिक विसंगति को भी बनाया आधार

शुक्ला ने यह भी कहा कि नया कानून संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत बना है। यह अनुच्छेद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में है। लेकिन धारा 16 सेवा शर्तों को लेकर है। इसे 324(2) के तहत पारित कानून में शामिल करना गलत है।

दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, न्यूनतम पारा 3-4 डिग्री तक लुढ़का, एक्यूआई अब भी लाल निशान में

नोएडा। दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में रात के समय पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड के चलते सुबह और रात में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी से 14 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इन दिनों अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री और न्यूनतम 3 से 4 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.ठंड को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन 15 जनवरी तक नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है।

चुनाव आयोग पर सीएम ममता के गंभीर आरोप, कहा- 20 वर्षों के वैधानिक सुधार की अनदेखी कर रहा ईसी

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, 'आयोग अपने ही 20 वर्षों के वैधानिक सुधारों की अनदेखी कर रहा है, जिससे मतदाताओं को अपनी पहचान दोबारा स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।' बता दें कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी एक अन्य पत्र में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समक्ष कई गंभीर मुद्दे उठाए थे।

चुनाव आयुक्त को लिखा पांचवां पत्र

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को सोमवार को एक और पत्र लिखा है। यह

उनका पांचवां पत्र है। इसमें उन्होंने वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (एसआईआर) प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों पर चिंता जताई है।

क्या बोलीं सीएम ममता बनर्जी?

ममता बनर्जी का दावा है कि 2002 की वोटर लिस्ट को डिजिटल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया गया, जिससे गंभीर गलतियां हुई हैं। उनका कहना है कि इन तकनीकी खामियों की वजह से असली वोटरों को गलत तरीके से 'विसंगति' वाली श्रेणी में डाल दिया गया है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

चुनाव आयोग पर आरोप

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह अपनी ही पुरानी प्रक्रियाओं की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में जो सुधार हुए थे, उन्हें दरकिनार कर वोटरों को फिर से अपनी पहचान साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने इसे मनमाना और संविधान की भावना के खिलाफ बताया।

सुनवाई प्रक्रिया पर सवाल

बनर्जी ने यह भी कहा कि एसआईआर के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की कोई रसीद नहीं दी जा रही है। उन्होंने सुनवाई प्रक्रिया को पूरी तरह मशीनी और संवेदनहीन बताया। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया मानवीय संवेदनाओं से खाली है और लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए, CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा- 94 फीसदी लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने मोदी सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता कन्नन गोपीनाथ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग स्कैम करने में इतने स्किल्ड हो चुके हैं कि अब 31 फरवरी को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कन्नन गोपीनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मोदी सरकार की एक योजना थी, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। हाल ही में इसकी CAG रिपोर्ट आई है, जिसमें 2015 से 2022 तक के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट ने PMKVY में भयंकर स्कैम का भंडाफोड़ किया है। एक प्रोग्राम था- नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। मोदी सरकार ने इसका नाम बदला, रिपैकेज किया और नाम रखा- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY। सरकार ने इस योजना के लिए 7 साल में 10 हजार करोड़ रुपए बांट दिए, जिसमें 94। 53 फीसदी लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी निकले हैं।

61 लाख ट्रेनरों की आधी-अधूरी जानकारी

वहीं, करीब 61 लाख ट्रेनरों की जानकारी आधी-अधूरी दी गई है। PMKVY के तहत ट्रेनिंग हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए Assessor होते हैं, लेकिन हमारे पास 97 फीसदी Assessor की कोई जानकारी नहीं है। ट्रेनिंग पूरी करने वालों के Email और मोबाइल नंबर लिए जाते हैं। यहां करीब 1 लाख ईमेल लिए गए हैं और 1 करोड़ लोगों के लिए वही ईमेल इस्तेमाल कर लिया गया है।

31 फरवरी को भी करवा रहे ट्रेनिंग

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नीलिमा मूविंग पिक्चर्स नाम की कंपनी ने PMKVY के तहत 33 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये कंपनी पिछले 5-6 साल से बंद है। ट्रेनिंग के तहत एक ही तस्वीर को अलग-अलग जगहों का बताकर इस्तेमाल किया गया और ट्रेनिंग देने की बात कही गई। जयपुर कल्चरल सोसाइटी नाम के ट्रेनिंग पार्टनर ने बताया है कि उन्होंने 31 फरवरी को ट्रेनिंग ऑर्गनाइज किया है।

7 साल में 10 हजार करोड़ का करप्शन

कन्नन गोपीनाथ ने आगे कहा कि ये लोग स्कैम करने में इतने स्किल्ड हो चुके हैं कि अब 31 फरवरी को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पिछले 7 साल में 10 हजार करोड़ रुपए ऐसे लोगों को बांटे गए हैं, जिनके न फोन नंबर हैं और न कोई सही Email एड्रेस। PMKVY के तहत ट्रेनिंग पार्टनर्स को एनरॉलमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट के समय पैसा दिया जाता रहा है।

इसरो की साल की पहली लॉन्चिंग असफल, 14 सैटेलाइट ले जा रहा पीएसएलवी सी-62 रॉकेट तीसरी स्टेज में रास्ते से भटका

नई दिल्ली, एजेंसी। 2026 की शुरुआत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के लिए खास अच्छी नहीं रही। भारत ने PSLV-C62 मिशन के साथ साल का पहला लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद ही रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया। सोमवार सुबह लॉन्च होने के 10 मिनट बाद ही रॉकेट ने अपने तय किए गए ऑर्बिट को नहीं मारा और रास्ते से भटक गया। मिशन में 16 सैटेलाइट्स शामिल थीं, जिनमें मुख्य था धरती का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1, इसके साथ आठ विदेशी सैटेलाइट्स भी थे, जो अब पूरी तरह से खो गए हैं।

पीएसएलवी की पहली बार लगातार दो बार विफलता

पीएसएलवी रॉकेट, जो ISRO के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में से एक माना जाता है, अब तक 64 मिशनों में केवल 4 बार ही फेल हुआ था। लेकिन यह पहली बार हुआ कि PSLV ने लगातार दो बार लॉन्च फेल हुआ। पिछले साल मई में पीएसएलवी सी61, जो EOS-09 सैटेलाइट लेकर गई थी, तीसरे स्टेज में समस्या के कारण ऑर्बिट तक नहीं पहुच पाया था।

रॉकेट में क्या हुआ- ISRO का बयान

इसरो चेयरपर्सन वी नारायणन ने बताया कि तीसरे स्टेज के अंत में रॉकेट के रोल रेट्स में ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली। इसके बाद फ्लाइट पाथ में डिविएशन देखा गया। उन्होंने कहा कि हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और जल्द ही जानकारी देंगे। इसरो ने अपने एक्स पोस्ट पर भी बताया कि PSLV-C62 मिशन को तीसरे स्टेज के अंत में एक अनहोनी का सामना करना पड़ा और इस पर गहन विश्लेषण शुरू कर दिया गया है।

पिछले पीएसएलवी फेल का कारण

PSLV-C61 के पिछले साल मई में फेल होने की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी। लेकिन ISRO चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा कि रॉकेट के प्रेशर चैम्बर में अचानक प्रेशर ड्रॉप हुआ था, जिसके कारण मिशन फेल हुआ। PSLV-C62 की विफलता का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और Failure Analysis Committee (FAC) इसे जांच रही है।

मिशन का अन्य उद्देश्य क्या था?

इस मिशन में सिर्फ धरती के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं था। साथ में स्पेनिश स्टार्टअप का KID कैप्सूल भी था, जो एक छोटे पैमाने का री-एंट्री प्रोटोटाइप है। इसे लॉन्च के दो घंटे बाद रॉकेट के चौथे स्टेज PS4 की मदद से डीकॉस्ट किया जाना था और साउथ पैसिफिक में सुरक्षित लैंडिंग करनी थी। PSLV-C62 मिशन ISRO की वाणिज्यिक लॉन्च क्षमता को भी मजबूत करता है। NSIL इसे कई घरेलू और विदेशी कस्टमर्स के लिए एक ही मिशन में लॉन्च सर्विस देने के लिए इस्तेमाल करता है। यह मिशन पूरी तरह से ISRO की तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताओं को दिखाता है।

इमरान मसूद बोले- 'बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में भी सोचे सरकार, इंदिरा गांधी होतीं तो...'

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। सहारनपुर जिला कांग्रेस कार्यालय सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर केक काटा गया और उनकी दीर्घायु की कामना की गई।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने कहा कि सरकार को बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता से सोचना चाहिए।

इंदिरा गांधी होतीं तो अलग जवाब देतीं

इमरान मसूद ने कहा कि यदि आज इंदिरा गांधी होतीं तो बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने बांग्लादेश को डीजल देने का समझौता किया है, जबकि बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाए तो बांग्लादेश घुटनों पर आ जाएगा।

मनरेगा को कमजोर किया गया

मनरेगा पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा ने इसे अपनी विफलताओं का स्मारक बताया था, लेकिन कोरोना काल में यही योजना गरीबों और मजदूरों के लिए संजीवनी बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए हैं और नए नियमों में राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है।

वोट कटौती पर जताई चिंता

एसआईआर और वोट कटने के मुद्दे पर इमरान मसूद ने कहा कि अब तक करीब 2.70 करोड़ लोगों के वोट काटे जा चुके हैं। लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए फार्म-6 भरें और लोकतंत्र की रक्षा करें।

कांग्रेस के 70 वर्षों के कार्य गिनाए

प्रेसवार्ता के दौरान इमरान मसूद ने कांग्रेस के 70 वर्षों के शासनकाल में किए गए विकास कार्यों को भी सामने रखा और भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया।

ये रहे मौजूद

इस मौके पर जिलाध्यक्ष संदीप राणा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी, प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू, पूर्व जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली समेत अनेक कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।

खेल-कूद में है रुचि तो अब हैं रोजगार के अवसर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। बच्चों को अक्सर सुनना पड़ता है कि पढ़ोगे-लिखोगे... बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे... बनोगे गंवार। लेकिन बदलते दौर के साथ स्कूलों में इस क्षेत्र को एक कौशल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। अब शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में रोजगार का एक अच्छा जरिया बनकर उभर रहा है। प्रशिक्षित लोगों के लिए सफल खिलाड़ी बनने के अलावा स्कूल-कॉलेज, खेल अकादमी, व्यायाम केंद्रों और अस्पताल आदि में प्रशिक्षक के रूप में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक, कोच, खेल अकादमियों में कोच, फिटनेस केंद्रों में प्रशिक्षक या न्यूट्रिशनिस्ट, खेल चिकित्सक, फ़िज़ियोथेरपी विशेषज्ञ और स्पॉर्ट्स इंवेंट्स में प्रबंधक, कमेंटेटर इत्यादि कई क्षेत्र हैं जहां उन्हें रोजगार मिल रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त किए लोगों को रोजगार मुहैया करना है। इंटर पास करने के बाद शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए भारत सरकार विभिन्न कोर्स चलाती है,जैसे शारीरिक शिक्षा से बीए, बीपीएस, बीए पास करने के बाद बीपीएड, डीपीएड, उसके बाद एमपीएड यूजीसी नेट जेआरएफ, पीएचडी आदि कोर्स बच्चे करके अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। यह जानकारी आनन्द सिंह ने दी, जो शारीरिक शिक्षा से बीए, बीपीएड, एमपीएड, यूजीसी नेट, नेशनल फेलोशिप किए है वर्तमान में इंटर कालेज में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के अध्यापक हैं।

द वॉयस ऑफ़ अवध प्रतियोगिता का दूसरा आडिशन सम्पन्न

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। द वॉयस ऑफ अवध इस क्षेत्र में लोक गायन की छिपी प्रतिभाओं को पहचानने का महत्वपूर्ण अवसर है। अवधी और भोजपुरी गीतों पर केंद्रित इस आयोजन में हम गांव की मिट्टी की महक महसूस कर सकते हैं। यह बातें राणा प्रताप पीजी कालेज के प्रबंधक एडवोकेट बालचंद्र सिंह ने कही। सत्यधाम आश्रम और राणा प्रताप पीजी कॉलेज के तत्वावधान में क्षत्रिय भवन में आयोजित अवधी और भोजपुरी लोकगीतों की प्रतियोगिता द वायस आफ अवध को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के आयोजक सत्यधाम आश्रम के गद्दीधीश आचार्य, सत्यसमदर्शी देवेंद्र कविराजदेव महाराज ने बताया कि प्रतियोगिता में अवध क्षेत्र के 18 जनपदों के कुल 73 बच्चों ने भाग लिया जिसमें से 30 प्रतिभागी चयनित हुए। इसके लिए दोनों राउंड मिलाकर कुल साठ प्रतिभाओं का चयन किया गया है। इनकी सूची जल्द ही सार्वजनिक की जायेगी । अंतिम रूप से टॉप 12 ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित होंगे जिसमें से तीन प्रतिभागियों प्रथम, द्वितीय और तृतीय को आकर्षक पुरस्कार देकर "द वायस आफ अवध" के खिताब से नवाजा जाएगा। विशिष्ट अतिथि असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह रवि ने कहा कि लोकगीत पीढ़ियों से चली आ रही एक मौखिक विरासत है जिसे गांव से जुड़ी महिलाएं सहेजती रही हैं। आज जब लोक परम्परायें संकट में हैं इन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है । महाविद्यालय आई क्यू ए सी निदेशक प्रोफेसर इन्द्रमणि कुमार ने कहा कि अच्छी गायकी के लिए अच्छा स्वर, सधा सुर, संगीत की समझ, सातत्य, समर्पण, साधना और संवेदनशीलता का सामंजस्य जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश कुमार त्रिपाठी व संचालन कवि लोकेश श्रीवास्तव ने किया। प्रतियोगिता के निर्णायक भोजपुरी के चर्चित गायक नंदन, चंदन और अमित यादव दीपू ने अपने गीतों से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए निष्पक्ष निर्णय दिया। इससे पूर्व अतिथियों ने सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर निर्देशक विनय पाण्डेय, अन्नू यादव, कवि अभिमन्यु शुक्ल तरंग, प्रबंधक सुधा देव जी, पंकज चौरसिया, बृजकुमार भारती, जादूगर संजय घायल, कवि धर्मराज, अंतिमा तिवारी, पार्वती पाण्डेय, राजन विश्वकर्मा, चंद्रमणि मौर्य, बाबुल यादव, मनीष तिवारी, पूनम पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का हुआ शुभारंभ

सुल्तानपुर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर जनपद में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की विधिवत शुरुआत कर दी गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि यह अभियान 12 जनवरी से 29 जनवरी तक जिले के सभी विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर चौपाल एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर मनरेगा श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पत्र ग्राम प्रधानों, पूर्व प्रधानों, रोजगार सेवकों एवं श्रमिकों तक पहुँचाया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं के माध्यम से मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के महत्व पर विस्तार से चर्चा की जाएगी तथा मजदूरों को उनके संवैधानिक रोजगार अधिकारों की जानकारी दी जाएगी।

शराब पीने पर टोका, गुस्से में पति ने प्रेग्नेंट पत्नी और डेढ़ साल के बेटे को मार डाला, फिर फूट-फूटकर रोया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां घाटमपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर (शारदेपुर) गांव में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी और महज डेढ़ साल के मासूम बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है।

जानकारी के अनुसार, गोपालपुर गांव के मजरा शारदेपुर निवासी सुरेंद्र यादव उर्फ स्वामी ट्रक खलासी का काम करता है। वह शराब पीने का बेहद आदि है। सुरेंद्र की शादी साल 2021 में फतेहपुर निवासी रूबी से हुई थी। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि शादी के बाद से ही सुरेंद्र की शराब पीने की आदत को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर मारपीट और विवाद होता रहता था।

गुस्से में बना हैवान, फिर खुद ही लगा रोने

बीती रात सुरेंद्र जब शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा, तो पत्नी रूबी ने उसका विरोध किया। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सुरेंद्र ने आपा खो दिया। उसने पास रखे धारदार हथियार से पहले अपनी गर्भवती पत्नी रूबी का गला रेत दिया। इसके बाद घर में मौजूद अपने ही डेढ़ साल के मासूम बेटे की भी बेरहमी से गर्दन काट दी।

ग्रामीणों ने बताया कि घटना के कुछ देर बाद जब वे सुरेंद्र के घर पहुंचे, तो वह खून से सने कपड़ों में घर के बाहर बैठकर रो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्या करने के बाद उसे पछतावा हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसे भनक लगी कि ग्रामीणों ने पुलिस को फोन कर दिया है, वह मौका पाकर वहां से फरार हो गया।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत

दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के जॉइंट सीपी आशुतोष कुमार, डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी और एसीपी कृष्णकांत यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आरोपी की तलाश जारी

एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण पति-पत्नी के बीच शराब को लेकर होने वाला क्लेश सामने आया है। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस की कई टीमें फरार आरोपी सुरेंद्र उर्फ स्वामी की तलाश में दबिश दे रही हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कम किराया, हवाई जहाज जैसी सुविधाएं! बिहार के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का ऐलान

लखनऊ। बिहार के रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बिहार को 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का उपहार देंगे। ये ट्रेनें पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक का सफर तय करेंगी, जिससे बिहार के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

रेलवे के इस नए कदम से बिहार में अमृत भारत ट्रेनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 18 हो जाएगी। 'अमृत भारत' ट्रेनें अपनी रफ्तार और 'पुश-पुल' तकनीक के लिए जानी जाती हैं, जिससे यात्रा का समय कम होता है और झटके कम लगते हैं। इन ट्रेनों में आधुनिक इंटीरियर, चार्जिंग पॉइंट्स और बेहतर सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं।

इन 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का जानें पूरा रूट और स्टॉपेज-

1- डिब्रूगढ़-गोमती नगर (लखनऊ) अमृत भारत (15949/15950): यह साप्ताहिक ट्रेन असम से लखनऊ के बीच चलेगी। बिहार में यह ट्रेन किशनगंज, कटिहार, नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर, छपरा और सीवान जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इससे मिथिला और सीमांचल के लोगों को यूपी जाना आसान होगा।

2- बनारस-सियालदह अमृत भारत (22588/22587): यह ट्रेन हफ्ते में तीन दिन चलेगी। बनारस से यह रविवार, गुरुवार और शुक्रवार को रवाना होगी, जबकि सियालदह से सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। बिहार की राजधानी पटना के यात्रियों के लिए यह ट्रेन सीधे बंगाल और वाराणसी जाने का बेहतरीन विकल्प बनेगी।

3- हावड़ा-आनंद विहार (दिल्ली) अमृत भारत (13065/13066): दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए यह साप्ताहिक ट्रेन एक बड़ी राहत है। बिहार में इसका ठहराव भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड और गया में दिया गया है। इससे दक्षिण बिहार के जिलों को सीधे दिल्ली की तेज कनेक्टिविटी मिलेगी।

4- पनवेल (मुंबई)-अलीपुरद्वार अमृत भारत (11031/11032): मुंबई जाने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण ट्रेन होगी। यह पनवेल से सोमवार और अलीपुरद्वार से गुरुवार को चलेगी। बिहार में इसका रूट काफी विस्तृत है, जिसमें बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और कटिहार जैसे स्टेशन शामिल हैं।

मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

इन ट्रेनों के संचालन से न केवल दिल्ली और मुंबई जाना आसान होगा, बल्कि बंगाल और उत्तर प्रदेश के साथ व्यापारिक और सामाजिक संबंध भी मजबूत होंगे। रेलवे बोर्ड के अनुसार, इन ट्रेनों के शुरू होने से मौजूदा ट्रेनों पर दबाव कम होगा और वेटिंग लिस्ट की समस्या से भी निजात मिलेगी।

आयुक्त अयोध्या मंडल के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क

सुल्तानपुर। अयोध्या मंडल के आयुक्त महोदय के जनपद भ्रमण को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा विस्तृत निरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। यह दौरा आज 13 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं एवं संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार आयुक्त सबसे पहले ग्राम चौपाल एवं पंचायत भण्डरा, विकास खंड कूरेभार में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। इसके उपरांत प्राथमिक विद्यालय भण्डरा पर मध्यान्ह भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत राजकीय बालिका आश्रय गृह, पलाही व दूध का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद विकास खंड कूरेभार के ग्राम सिसवार में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण प्रस्तावित है। दौरे के अंतिम चरण में नवीन सभागार, कलेक्ट्रेट में माननीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड आधारित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक तथा कानून एवं राजस्व व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

एक टिकट, एक बार सिक्योरिटी चेक और मेरठ से पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट... 4 घंटे नहीं दो घंटे में पूरा होगा सफर

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ से दिल्ली के द्वारका तक का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। अब यात्रियों को सिर्फ एक ही टिकट लेना होगा और एक बार सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरने के बाद सीधे मेरठ से एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। नमो भारत से मेरठ से दिल्ली के अशोक नगर पहुंचने पर इंटरचेंज होगा। फिर यहां से द्वारका के लिए डायरेक्ट मेट्रो ले सकते हैं, जो एयरपोर्ट से भी कनेक्ट होती है। इस तरह जहां पहले सड़क मार्ग से जाने पर ये दूरी तय करने में करीब 4 घंटे का समय लगता था। अब नमो भारत और मेट्रो की मदद से 2 घंटे में लोग मेरठ से एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं।

दरअसल, नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के बीच इंटरचेंज करने वाले यात्रियों के लिए सिंगल प्वॉइंट सिक्योरिटी चेकिंग की शुरुआत की गई है। नमो भारत के न्यू अशोक नगर स्टेशन से मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए यात्रियों को दोबारा चेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसकी शुरुआत दोनों नेटवर्क के बीच यात्रियों को राहत देने और आरामदायक सफर के लिए की गई है।

सिंगल प्वॉइंट सिक्योरिटी चेकिंग की सुविधा

NCRTC अधिकारी के मुताबिक सिंगल प्वॉइंट सिक्योरिटी चेकिंग की सुविधा शुरू होने के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब जो यात्री दिल्ली मेट्रो से नमो भारत के जरिए मेरठ की ओर सफर करेंगे और अशोक नगर पर इंटरचेंज के समय दोबारा सिक्योरिटी चेक से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसी तरह नमो भारत से आने वाले यात्रियों को नोएडा की ओर मेट्रो पकड़ने के लिए अलग से चेकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दोनों स्टेशनों को जोड़ने वाले इंटरचेंज फुट ओवर ब्रिज और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-2 पर नया सिक्योरिटी चेक प्वाइंट बनाया गया है। इस व्यवस्था से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा, क्योंकि बार-बार होने वाली चेकिंग की वजह से लगने वाली लंबी लाइन में लगने की दिक्कत खत्म होंगी और स्टेशन पर लगने वाले समय की बचत होगी।

इंटीग्रेटेड क्यूआर टिकटिंग सिस्टम लागू

आगे चलकर इस फुट ओवर ब्रिज पर ट्रैवल लेटर लगाने की भी योजना है, जिससे भारी सामान के साथ यात्रा करने वालों को आसानी होगी। इसके अलावा एनसीआरटीसी और दिल्ली मेट्रो के बीच इंटीग्रेटेड क्यूआर टिकटिंग सिस्टम पहले ही लागू किया जा चुका है। अब यात्री किसी एक मोबाइल ऐप के जरिए दोनों के टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे टिकट काउंटर पर खड़े होने की परेशानी भी खत्म हो गई है।

कांग्रेसियों ने उत्साहपूर्वक मनाया प्रियंका गांधी का जन्मदिन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं वायनाड की सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिवस जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर सादगी, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 51 किलो का केक काटकर एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया तथा प्रियंका गांधी वाड्रा के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और जन सरोकारों की सशक्त प्रतीक हैं। वे निरंतर आमजन, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों की आवाज़ बनकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही हैं। उनका संघर्ष और संवेदनशील नेतृत्व देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शकील अंसारी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा वर्तमान समय में देश की करोड़ों महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उनका साहस, संघर्ष और जनसमर्पण समाज के हर वर्ग को आशा और विश्वास प्रदान करता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जफर खान ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा सच्चे अर्थों में जनसंघर्ष की प्रतीक हैं,

उनका उप्र में पिछला कार्यकाल संघर्षों से भरा रहा है। वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी ने कहा प्रियंका गांधी जी वर्तमान सरकार के अहंकार के विरुद्ध मजबूती से खड़ी होकर जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं और गरीब, मजदूर व किसानों के हक की आवाज़ बुलंद कर रही हैं।

जन्मदिन के अवसर पर सेवादल के प्रदेश सचिव दिनेश मिश्रा व सुरेश चंद्र मिश्रा द्वारा कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस मौके राहुल त्रिपाठी,नफीस फारूकी, वरुण मिश्र,सलाहुद्दीन हाशमी, रणजीत सिंह सलूजा, हौसिला प्रसाद भीम,जय प्रकाश पाठक, आवेश अहमद, ममनून आलम, सुब्रत सिंह, नरेश चंद्र उपाध्याय, उमाकांत त्रिपाठी, मनीष तिवारी, विनय त्रिपाठी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

जीएसटी इंस्पेक्टर के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, यूपी एसटीएफ ने किया भंडाफोड़... सरकार को ऐसे लगाई 100 करोड़ की चपत

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक बार फिर जीएसटी चोरी के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिंडिकेट ने सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये की चपत लगाई है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें केंद्रीय जीएसटी विभाग के एक तैनात इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल का भी नाम सामने आया है, जिसे अब आरोपी बनाया गया है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, यह गिरोह फर्जी कंपनियां (शेल कंपनियां) बनाने, जाली चालान (फेक इनवॉइस) जारी करने और फर्जी ई-वे बिल तैयार करने के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत दावा कर रहा था। इन फर्जी लेन-देन से सरकार के खजाने को करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान

हुआ है। गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले की जांच एसटीएफ ने संभाली।

एसटीएफ ने चार आरोपियों को दबोचा

एसटीएफ ने हरदीप सिंह उर्फ प्रिंस (नई दिल्ली स्थित स्क्रैप कारोबारी), जितेंद्र झा, पुनीत अग्रवाल और शिवम सिंह को गिरफ्तार किया है। ये सभी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जांच में पता चला कि गिरोह ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में दर्जनों फर्जी फर्में रजिस्टर कराई थीं।

इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल की कथित मिलीभगत

जांच में खुलासा तब हुआ जब वर्तमान में नई दिल्ली में तैनात केंद्रीय जीएसटी इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल की भूमिका उजागर हुई। एसटीएफके अधिकारियों का दावा है कि इंस्पेक्टर ने इस गिरोह को विभागीय संरक्षण दिया और रिश्वत लेकर कई गड़बड़ियां कीं।

पुनीत अग्रवाल से जुड़ी पूरी तरह फर्जी फर्म एडॉन ऑटोमोबाइल को करीब तीन महीने पहले निलंबित कर दिया गया था। लेकिन इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद इसे बहाल कर दिया गया। इस काम के बदले कथित तौर पर 40,000 रुपये की रिश्वत ली गई।

अधिकारियों का कहना है कि इंस्पेक्टर ने न सिर्फ निलंबित फर्मों को बहाल किया, बल्कि फर्जी संस्थाओं को जांच से बचाने और रिकॉर्ड में हेरफेर करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। मोहित अग्रवाल फिलहाल फरार हैं और STF की टीमें उन्हें ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं।

एक आरोपी हरियाणा का

जांच में एक हरियाणा निवासी दलाल आलोक का नाम भी सामने आया है, जिसने कथित तौर पर हरदीप सिंह को एकमुश्त कमीशन पर फर्जी फर्में उपलब्ध कराईं। पुनीत अग्रवाल के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट्स में भुगतान, कमीशन और रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़ी बातचीत मिली है, जो इस पूरे नेटवर्क की गहराई को दर्शाती है।

एसटीएफ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच का दायरा अब यूपी के अलावा पड़ोसी राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की प्रबल संभावना है।

राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप : गार्गी ने बढ़ाया लखनऊ का मान

क्लासिकल वर्ग में जीता स्वर्ण पदक

राष्ट्रीय बैटल डांस स्पोटर्स प्रतियोगिता–2026 का समापन, उत्तर प्रदेश ओवरऑल चैंपियन घोषित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बैटल डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय बैटल डांस स्पोर्ट्स प्रतियोगिता–2026 का समापन रविवार को देर शाम संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय, सदर बाजार, लखनऊ में हुआ ज्ञात हो कि प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा 10 जनवरी को हुआ था वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि अनूप गुप्ता (सदस्य विधान परिषद) रहे।

क्लासिकल वर्ग में गार्गी ने मारी बाज़ी : नन्ही बाल नृत्यांगना गार्गी द्विवेदी ने क्लासिकल के वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है । उनकी मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब सराहना प्राप्त की और इस दौरान वहां मौजूद दर्शकों को तालियां बजाने को मज़बूर कर दिया। बता दें कि गार्गी द्विवेदी सिटी मोंटेसरी स्कूल की कक्षा दो की छात्रा हैं और अब तक कथक एवं लोकनृत्य श्रेणी में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

इसके अलावा अन्य विजेताओं में ध्वनि मिश्रा, लावण्या काबरा, योग्या वर्मा, सांभवी अग्रवाल, स्तुति खन्ना, स्तुति मिश्रा, प्रिशा, अविका, सताक्षी, अरुणिमा, ईशित्वा, आयरा राठौर एवं साक्षिका पाठक, आराध्या वर्मा एवं अस्मिता सिंह रहे। चैंपियनशिप में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों का मूल्यांकन तकनीक, प्रस्तुति, समन्वय, तालमेल और रचनात्मकता के आधार पर किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि आनंदेश्वर पाण्डेय (सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश ओलंपिक कमिटी) उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए आयोजन समिति को इस सफल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में अंकुर अग्रवाल (ट्रस्टी, संस्कृत पाठशाला समिति) की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही अर्जुन अवॉर्डी रचना गोविल की विशेष उपस्थिति समारोह का प्रमुख आकर्षण रही, जिनकी मौजूदगी से खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

समापन अवसर पर घोषित परिणामों में उत्तर प्रदेश को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। प्रतियोगिता के दौरान शास्त्रीय नृत्य, मॉडर्न मिक्सर, फ्रीग्न, एक्रोयोगा सहित विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का सफल आयोजन बैटल डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। आयोजन समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. बी. पंत ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों, अभिभावकों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

रोहतास अपार्टमेंट में आग से अफरा–तफरी, छत से कूदने पर महिला की मौत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। अयोध्या रोड स्थित नीलगिरी चौराहा क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। रोहतास अपार्टमेंट, रविन्द्रपल्ली में फ्लैट संख्या 73 और 74 में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना सुबह करीब 07:09 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद गाजीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक, HAL चौकी प्रभारी तथा रात्रि अधिकारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे।मौके पर जांच में सामने आया कि दोनों फ्लैटों के स्वामी हसीन अहमद हैं। आग फ्लैट संख्या 74 में लगी, जहां सैय्यद मोहम्मद अम्मार रिजवी अपने परिवार के साथ निवासरत थे। आग लगने के दौरान घबराहट में उनकी पत्नी निदा रिजवी, उम्र लगभग 45 वर्ष, आग के भय से छत से कूद गईं। इस दौरान उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस द्वारा तत्काल उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।घटना में सैय्यद मोहम्मद अम्मार रिजवी, उम्र लगभग 50 वर्ष, भी झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं उनकी पुत्री जारा रिजवी, उम्र लगभग 20 वर्ष, को फायर ब्रिगेड की मदद से कमरे से सकुशल बाहर निकाल लिया गया।सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। वर्तमान में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस द्वारा मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना के कारणों की जांच जारी है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में 'भारत बौद्धिक्स' योजना के अंतर्गत 21 पुस्तकों का विमोचन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में कला, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों पर आधारित 21 पुस्तकों का विमोचन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने की। यह आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की महत्त्वाकांक्षी 'भारत बौद्धिक्स' योजना के अंतर्गत किया गया।उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा और नैतिक मूल्य एक-दूसरे के पूरक हैं और केवल डिग्री आधारित शिक्षा समाज को सही दिशा नहीं दे सकती। भारतीय शिक्षा परंपरा सदैव चरित्र निर्माण, कर्तव्यबोध और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित रही है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि यह नीति भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं और कौशल आधारित शिक्षा को केंद्र में रखती है।मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व पर्यावरणीय संकट, मानसिक तनाव और नैतिक मूल्यों के क्षरण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनका समाधान भारतीय दर्शन और ज्ञान परंपरा में निहित है। योग, आयुर्वेद और भारतीय जीवन मूल्यों को आज वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को अब ज्ञान का उपभोक्ता नहीं, बल्कि ज्ञान का मार्गदर्शक बनना होगा और 'भारत बौद्धिक्स' जैसी पहलें युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करेंगी।

मकर संक्रांति पर अवकाश की तिथि बदली, 15 जनवरी 2026 को रहेगा प्रदेशभर में सार्वजनिक अवकाश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर पूर्व में घोषित अवकाश की तिथि में संशोधन करते हुए 15 जनवरी 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह फैसला लिया गया है कि पहले 14 जनवरी को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर अब 15 जनवरी, गुरुवार को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी।शासन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी 2026 को निगोशिएबुल इंस्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इससे पूर्व 17 नवम्बर 2025 को जारी विज्ञप्ति में 14 जनवरी को निर्बन्धित अवकाश निर्धारित किया गया था, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है।

एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को एआई हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नेतृत्व में आयोजित एआई एवं स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन के अवसर पर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एआई इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।इस क्रम में इंडियाएआई मिशन और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपी डेस्को), लखनऊ के मध्य एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। यह

एमओयू आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव और इंडियाएआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह के बीच संपन्न हुआ। यह समझौता केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।इस अवसर पर प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने कहा कि इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत की गई यह पहल प्रदेश के युवाओं को भविष्य के लिए आवश्यक डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास, नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर लगातार कार्य कर रही है।यूपी डेस्को की प्रबंध निदेशक नेहा जैन ने बताया कि इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को नोडल प्रशासकीय विभाग और यूपी डेस्को को राज्य की नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह व्यवस्था प्रदेश में एआई आधारित पहलों के प्रभावी, समन्वित और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि इंडियाएआई मिशन के तहत प्रदेश में कुल 65 डेटा एवं एआई लैब स्थापित किए जाने की योजना है। इनमें लखनऊ और गोरखपुर स्थित एनआईईएलआईटी केंद्रों में दो डेटा एवं एआई लैब पहले से संचालित हैं, जबकि पीलीभीत में एक डेटा एवं एआई लैब उद्योग साझेदारी के माध्यम से स्थापित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 49 डेटा एवं एआई लैब को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए संशोधित समय सारिणी जारी कर दी है। आयोग के अनुसार अब 20 फरवरी 2026 तक पंचायतों से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में प्राप्त सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही हस्तलिखित पाण्डुलिपियां तैयार कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराई जाएंगी तथा संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन और निस्तारण की कार्यवाही भी इसी अवधि में पूरी की जाएगी।राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के तहत 21 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों के कम्प्यूटरीकरण की तैयारी की जाएगी।

लखनऊ नगर निगम की सख्ती, करोड़ों के गृहकर बकाए पर सरकारी संस्थान सील

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम द्वारा बड़े बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर सोमवार को नगर निगम जोन–4 की टीम ने एक अहम कदम उठाते हुए सरकारी विभाग के विरुद्ध भी सीलिंग की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कर वसूली के मामले में किसी भी स्तर पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।जोन–4 की यह कार्रवाई जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी के नेतृत्व में की गई, जिसमें नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स (एनबीएफजीआर) परिसर को सील कर दिया गया। नगर निगम के अनुसार उक्त संस्थान पर लंबे समय से 1 करोड़ 36 लाख 65 हजार 932 रुपये का गृहकर बकाया था। बकाया वसूली को लेकर कई बार नोटिस

और पत्राचार किए गए, लेकिन निर्धारित समयावधि में कर जमा न होने के कारण नगर निगम को यह कठोर कदम उठाना पड़ा।नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि राजस्व वसूली को लेकर अब किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चाहे बकाएदार निजी हो या सरकारी विभाग, नियमों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।सीलिंग की इस कार्रवाई के दौरान कर अधीक्षक, कर निरीक्षक सहित नगर निगम के अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों, संस्थानों और विभागों से अपील की है कि वे समय से अपने करों का भुगतान करें, ताकि इस तरह की अनिवार्य और कड़ी कार्रवाई से बचा जा सके।

राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता–2026 का लखनऊ में शुभारंभ, 18 मंडलों के 464 युवा प्रतिभागी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक, रोजगारपरक और वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इंडिया स्किल्स कंपटीशन–2026 के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में लखनऊ में आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का सोमवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 18 मंडलों से आए 464 युवाओं ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया।राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता के पहले दिन लखनऊ स्थित नौ प्रमुख संस्थानों की 16 कार्यशालाओं में छह विभिन्न स्किल्स के अंतर्गत प्रतिभागियों का ओरिएंटेशन आयोजित किया गया।

मंत्री राकेश सचान ने खादी, हथकरघा एवं एमएसएमई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 8 तिलक मार्ग, लखनऊ के सभागार में विभागीय योजनाओं के लिए बजट में की गई व्यवस्था के सापेक्ष व्यय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

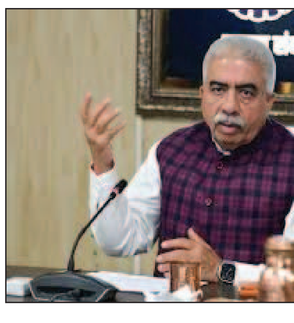

समीक्षा बैठक में एमएसएमई विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योगी सरकार की प्राथमिक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो और सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।मंत्री ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त सभी प्रशिक्षुओं को टूलकिट का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और प्रभारी मंत्री की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में मंत्री राकेश सचान ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तहसील और ब्लॉक स्तर तक और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने, प्रशिक्षण और जागरूकता कैंपों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने और योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।मंत्री ने खादी उत्पादन को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के उद्देश्य से खादी के कंबल और अन्य उत्पादों को आधुनिक परिवेश और बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने, गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने खादी से जुड़े कारखानों का नियमित निरीक्षण और कार्यप्रणाली के सुदृढ़ीकरण के निर्देश भी दिए।साथ ही, मंत्री ने निष्क्रिय समितियों की भूमि एवं परिसंपत्तियों का भौतिक निरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही करने, सरकारी भूमि के उचित उपयोग, अवैध कब्जों से मुक्त कराने और परिसंपत्तियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए।मंत्री राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में रोजगार सृजन, पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण और आधुनिक तकनीक के समावेश के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, आवंटित बजट का शत-प्रतिशत प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और परिणामोन्मुखी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बीबीएयू में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी चेतना का सशक्त संदेश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। स्थित बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय 'आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु युवा शक्ति और स्वदेशी भावना: स्वामी विवेकानंद का जीवन और दर्शन' रखा गया, जिसमें युवाओं की भूमिका, स्वदेशी सोच और राष्ट्रनिर्माण पर व्यापक विमर्श हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे, जबकि अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की।कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं बाबासाहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। विश्वविद्यालय कुलगीत के पश्चात

आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का पौधा, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने स्वागत संबोधन में राष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है और भारतीय संस्कृति ने विश्व को हर क्षेत्र में दिशा दी है। उन्होंने कहा कि अनेक आक्रमणों के बावजूद भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनी रहीं, यही कारण है कि आज विश्व भारत को सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से एक केंद्रबिंदु के रूप में देखता है। स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना भारत की पहचान है और आज देश कृषि से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने युवाओं से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए युवाओं से इनका लाभ उठाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की।कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को स्वामी विवेकानंद के भारत-स्वप्न से जोड़ते हुए कहा कि इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करना होगा। उन्होंने आत्मचिंतन, अनुशासन और भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। 'नर सेवा ही नारायण सेवा है' के विचार का उल्लेख करते हुए उन्होंने समाज के वंचित वर्गों से जुड़कर समग्र विकास की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता बताई और कहा कि शिक्षण संस्थान विचारों के केंद्र होते हैं, जहां से सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कश्मीरी लाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद इस सदी के महानतम व्यक्तित्वों में से एक थे, जिन्होंने युवाशक्ति को जागृत किया।

मिशन शक्ति 5 .0 के तहत हसनगंज में पिंक बूथ टीम का जागरूकता अभियान, महिलाओं और छात्राओं को साइबर सुरक्षा व हेल्पलाइन की जानकारी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 12 जनवरी 2026 को थाना हसनगंज की मिशन शक्ति एवं पिंक बूथ टीम ने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं, छात्राओं और बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव तथा विभिन्न सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।थाना हसनगंज की पिंक बूथ टीम ने पिंक स्कूटी के माध्यम से क्षेत्र का भ्रमण किया और आमने-सामने संवाद के जरिए महिलाओं व छात्राओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड,

बैंक धोखाधड़ी और फर्जी कॉल जैसे बढ़ते खतरों के प्रति सतर्क किया। पुलिस कर्मियों ने बताया कि डिजिटल लेन-देन और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों की आशंका भी बढ़ी है, ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।अभियान के दौरान महिलाओं को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने वाली सेवाओं की जानकारी दी गई। इसमें 112 आपातकालीन सेवा, 1090 महिला पावर लाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन और 181 महिला हेल्पलाइन के उपयोग और महत्व को सरल भाषा में समझाया गया। साथ ही महिला शक्ति केंद्रों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया, ताकि जरूरत पड़ने पर महिलाएं बिना संकोच सहायता प्राप्त कर सकें।

घर में नहीं दाने, मुहम्मद यूनुस चले पाकिस्तान से जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीद कर लाने

दक्षिण एशिया के सामरिक परिदृश्य में एक नई हलचल तब देखने को मिली जब पाकिस्तान ने दावा किया कि बांग्लादेश उसके साथ जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमान की खरीद में रुचि दिखा रहा है। हम आपको बता दें कि यह जानकारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सामने आई। इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और वायुसेना की क्षमताओं को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया कि बातचीत के दौरान जेएफ-17 जैसे बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमानों की संभावित बिक्री पर गंभीर विचार हुआ।

हम आपको बता दें कि जेएफ-17 थंडर एक हल्का, अपेक्षाकृत सस्ता और बहु उद्देश्यीय लड़ाकू विमान माना जाता है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया है। पाकिस्तान इसे लंबे समय से अपनी वायुसेना की रीढ़ के रूप में पेश करता रहा है। हालांकि बांग्लादेश की ओर से अब तक इस प्रस्ताव पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान का यह दावा ही क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा विश्लेषकों के लिए काफी है। इसी बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच वर्षों से बंद सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने पर भी सहमति बनी, जिसे आपसी संबंधों में नई गर्माहट के रूप में देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब बांग्लादेश की आंतरिक आर्थिक स्थिति दबाव में है और क्षेत्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है। देखा जाये तो बांग्लादेश का पाकिस्तान से जेएफ-17 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाना केवल एक रक्षा सौदे की खबर नहीं है, यह एक तेज और साफ संदेश है। यह संदेश है कि ढाका अब नए विकल्पों की ओर बढ़ने को तैयार है। सवाल यह नहीं है कि जेएफ-17 कितना सक्षम या सस्ता विमान है, असली सवाल यह है कि बांग्लादेश यह कदम क्यों उठा रहा है और इसके पीछे की मंशा क्या है।

सबसे पहले सामरिक दृष्टि से देखें तो जेएफ-17 चीन और पाकिस्तान की संयुक्त रणनीतिक सोच का उत्पाद है। यह विमान तकनीकी रूप से भले ही मध्यम श्रेणी का हो, लेकिन इसका राजनीतिक वजन कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ अपनी क्षमता के प्रतीक के रूप में पेश करता रहा है। ऐसे में बांग्लादेश द्वारा इस विमान में रुचि दिखाना सीधे तौर पर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में नई रेखाएं खींचने जैसा है। भारत की पूर्वी सीमाओं के पास पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी रक्षा सहयोग स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करता है। अब इससे भी बड़ा और चौंकाने वाला पहलू है बांग्लादेश की आर्थिक हालत। देश इस समय गंभीर आर्थिक दबावों से जूझ रहा है। महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, आयात खर्च और आम जनता की क्रय शक्ति में गिरावट जैसी समस्याएं साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे माहौल में लड़ाकू विमानों की खरीद कोई मामूली खर्च नहीं है। यह अरबों रुपये की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता होती है, जिसमें रखरखाव, प्रशिक्षण और भविष्य के उन्नयन का बोझ भी जुड़ा रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था सांसें गिन रही हो, तब आसमान में उड़ने वाले विमानों पर इतना भारी दांव क्यों लगाया जा रहा है? देखा जाये तो इस सवाल का जवाब राजनीति और संदेश में छिपा है। पाकिस्तान से हथियार खरीदना केवल तकनीकी फैसला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक कदम है। 1971 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध कभी सहज नहीं रहे। अब अचानक रक्षा सहयोग, सीधी हवाई सेवाएं और सैन्य बातचीत यह संकेत देती है कि ढाका पुराने अध्यायों को पीछे छोड़कर नए समीकरण गढ़ना चाहता है। लेकिन यह समीकरण किसके खिलाफ और किसके लिए है, यह सवाल अनदेखा नहीं किया जा सकता।

भारत के संदर्भ में यह घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के संबंध हाल के वर्षों में कभी सहयोग तो कभी तनाव के दौर से गुजरे हैं। सीमा, जल बंटवारा और राजनीतिक बयानबाजी ने रिश्तों को जटिल बनाया है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का बढ़ता रक्षा संवाद नई रणनीतिक चुनौती के रूप में उभर सकता है। यह केवल सैन्य संतुलन की बात नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय भरोसे की भी परीक्षा है। यह भी गौर करने लायक है कि चीन इस पूरी तस्वीर में खामोश लेकिन मजबूत भूमिका निभा रहा है। जेएफ-17 के जरिए चीन अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश की रक्षा व्यवस्था में अपनी पैठ बढ़ा सकता है। यानी यह सौदा तीन देशों की रणनीति का संगम बन सकता है, जहां आर्थिक रूप से दबाव में खड़ा बांग्लादेश खुद को एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बना रहा है।

विश्व में हिन्दी की बढ़ती साख: भारत में उपेक्षा क्यों?

ललित गर्ग

> हिंदी मात्र संवाद की भाषा नहीं है, वह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संवेदना और सामूहिक चेतना की वाहक है। यह लोक से उपजी, लोक में पली और लोक के लिए ही जीने वाली भाषा है।

विश्व में लगभग साठ-सत्तर करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, समझते या किसी न किसी रूप में उससे जुड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी की उपस्थिति निरंतर बढ़ रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसकी शुरुआत 1975 में नागपुर में हुई थी, आज एक वैश्विक वैचारिक आंदोलन का रूप ले चुका है। हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व हिंदी दिवस केवल एक औपचारिक या प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हिंदी भाषा की वैश्विक यात्रा, उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा, उसके सामने उपस्थित चुनौतियों और हमारे अपने राष्ट्रीय आचरण की विडंबनाओं पर गहन चिंतन का अवसर है। यह दिन हमें उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति कराता है जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी बोली गई थी और भारत की सांस्कृतिक आत्मा ने विश्व मंच पर अपनी मौलिक पहचान दर्ज कराई थी। आज स्थिति यह है कि हिंदी विश्व में सम्मान, स्वीकार्यता और लोकप्रियता की नई ऊँचाइयों को छू रही है, लेकिन अपने ही देश में वह अपेक्षा, उपेक्षा और संकोच के बीच झूलती दिखाई देती है। यही विरोधाभास विश्व हिंदी दिवस को और अधिक प्रासंगिक बना देता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में फैले हिंदी जानकारों, हिन्दीभाषियों को एकजुट करना, हिन्दी को विश्व स्तर पर स्थापित एवं प्रोत्साहित करना और हिंदी की आवश्यकता से अवगत कराना है। अंग्रेजी भाषा भले ही दुनियाभर के कई देशों में बोली है और लिखी जाती है लेकिन हिंदी हृदय की भाषा है। विश्व हिन्दी दिवस विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता पैदा करने तथा हिन्दी को अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का प्रभावी उपक्रम है।

हिंदी मात्र संवाद की भाषा नहीं है, वह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संवेदना और सामूहिक चेतना की वाहक है। यह लोक से उपजी, लोक में पली और लोक के लिए ही जीने वाली भाषा है। हिंदी का सबसे बड़ा गुण उसकी सहजता, सरलता और वैज्ञानिक संरचना है। यह ध्वन्यात्मक भाषा है, जिसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, जिससे इसे सीखना और अपनाना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। यही कारण है कि जिन देशों में भारतीय प्रवासी बसे हैं, वहां हिंदी ने सहज ही अपनी जड़ें जमा ली हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक हिंदी आज केवल भारतीयों की भाषा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवाद की भाषा बनती जा रही है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, बॉलीवुड, भक्ति साहित्य और डिजिटल माध्यमों ने हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, अंग्रेजी और मंदारिन चीनी के बाद, और भारत के साथ-साथ नेपाल, मॉरीशस, फिजी जैसे देशों में भी इसका व्यापक उपयोग है और यह विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो रही है।

विश्व में लगभग साठ-सत्तर करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, समझते या किसी न किसी रूप में उससे जुड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी की उपस्थिति निरंतर बढ़ रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसकी शुरुआत 1975 में नागपुर में हुई थी, आज एक वैश्विक वैचारिक आंदोलन का रूप ले चुका है। इन सम्मेलनों ने यह सिद्ध किया है कि हिंदी केवल भावनाओं या साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि विचार, विज्ञान, कूटनीति और वैश्विक संवाद की भी सक्षम भाषा है। हिंदी को वैश्विक मंच पर आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ प्रस्तुत करने का श्रेय यदि किसी भारतीय नेता को जाता है, तो वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया उनका भाषण केवल भाषण नहीं था, बल्कि वह एक सांस्कृतिक उद्घोषणा थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदी में भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शांति, निरस्त्रीकरण और मानवता जैसे गहन विषयों पर प्रभावी संवाद संभव है। उनके लिए हिंदी भावुक आग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्रबोध की सशक्त अभिव्यक्ति थी। उन्होंने हिंदी को सत्ता की भाषा बनाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे संवाद और आत्मगौरव की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में हिंदी की यात्रा कुछ हद तक धीमी अवश्य हुई, विशेष रूप से शासन और उच्च प्रशासनिक स्तर पर। अंग्रेज़ी को आधुनिकता, सफलता और वैश्विकता का प्रतीक मान लिया गया, जबकि हिंदी को प्रायः भावनात्मक या घरेलू दायरे में सीमित कर दिया गया। शिक्षा, न्यायपालिका, कॉर्पोरेट जगत और उच्च प्रशासन में हिंदी अपेक्षित स्थान नहीं बना सकी। हालांकि हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और सिनेमा ने इस दौर में भी अपनी सृजनात्मक ऊर्जा बनाए रखी, लेकिन नीतिगत स्तर पर हिंदी को वह प्राथमिकता नहीं मिल पाई जिसकी वह हकदार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिंदी ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ उपस्थिति दर्ज कराई है। वे विश्व के किसी भी मंच पर हिंदी में बोलने से संकोच नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जी-20 सम्मेलन, शंघाई सहयोग संगठन या प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम, हर जगह उनकी हिंदी यह संदेश देती है कि अपनी भाषा में बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का परिचायक है। नरेंद्र मोदी ने हिंदी को अनुवाद की बैसाखी के सहारे नहीं, बल्कि उसकी मौलिक शक्ति के साथ प्रस्तुत किया। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों में हिंदी को केंद्र में रखा गया, जिससे आम नागरिक का शासन से संवाद अधिक सुलभ और प्रभावी हुआ। सरकारी योजनाओं, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी की बढ़ती उपस्थिति ने यह सिद्ध किया कि तकनीक और हिंदी एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। इसके बावजूद यह एक कटु सत्य है कि हिंदी आज विश्व में जितनी प्रतिष्ठित हो रही है, उतनी ही अपने ही देश में उपेक्षित होती जा रही है। अंग्रेज़ी को सामाजिक प्रतिष्ठा और बौद्धिक श्रेष्ठता का पैमाना बना दिया गया है। माता-पिता अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाकर गर्व महसूस करते हैं, जबकि हिंदी माध्यम को हीन दृष्टि से देखा जाता है। यह समस्या भाषा की नहीं, मानसिकता की है। यह मानसिक गुलामी है, जो हमें अपनी ही भाषा से दूर करती जा रही है। राजनीतिक दल हिंदी की बात तो करते हैं, लेकिन उसे शिक्षा, न्याय और प्रशासन की मुख्यधारा में स्थापित करने के लिए ठोस इच्छाशक्ति का अभाव दिखाई देता है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा भी है, यह तथ्य अक्सर उपेक्षित रह जाता है। इसकी वर्णमाला उच्चारण विज्ञान पर आधारित है। इसमें नए शब्द गढ़ने और विदेशी शब्दों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है। संस्कृत से जुड़ी होने के कारण यह तकनीकी, दार्शनिक और वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण में पूरी तरह सक्षम है। हिंदी में भावनाओं की अभिव्यक्ति जितनी सहज है, उतनी ही तार्किक और बौद्धिक विमर्श की भी क्षमता है। यही कारण है कि हिंदी जनभाषा होते हुए भी वैश्विक संवाद की भाषा बनने की पूरी क्षमता रखती है। सच्चाई तो यह है कि देश में हिंदी अपने उचित सम्मान को लेकर जूझ रही है। राजनीति की दूषित एवं संकीर्ण सोच का परिणाम है कि हिन्दी को जो सम्मान मिलना चाहिए, वह स्थान एवं सम्मान आजादी के अमृत महोत्सव मना चुके राष्ट्र में अंग्रेजी को मिल रहा है। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की सहायता जरूर ली जाए लेकिन तकनीकी एवं कानून की पढ़ाई एवं राजकाज की भाषा के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी को प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी

वोट खरीद की योजनाएं

बुजुर्गों को पेंशन मिले, यह कल्याणकारी सोच है। मगर ऐसी सामाजिक सुरक्षा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को क्यों मिलनी चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को एक अलग सुविधा-प्राप्त वर्ग के रूप में रखने के प्रयासों के दुष्परिणाम पहले भी सामने आ चुके हैं।

बिहार की तर्ज पर असम सरकार ने भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में रुपया भेजने की योजना घोषित की है। वहां इसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना कहा जाएगा। इसके तहत 37 लाख महिलाओं के खाते में 8000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य के खजाने पर आएगा। अगले अप्रैल- मई में विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में भी होना है। तो वहां सरकार ने पहले अपने कर्मचारियों को लुभाने की योजना घोषित की है। तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिटायर्ड होने वाले राज्य सरकार के हर कर्मचारी को कम से कम अपने आखिरी वेतन का 50 फीसदी हिस्सा बतौर पेंशन मिले।

इसके लिए कर्मचारी को सिर्फ दस फीसदी योगदान करना होगा। अतिरिक्त सारा बोझ राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही रिटायर हो रहे कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक ग्रैच्युटी मिले, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल इन योजनाओं से राज्य सरकार पर 13 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। चूंकि पेंशन की रकम महंगाई दर के अनुपात में बढ़ेगी, इसलिए यह खर्च हर गुजरते वर्ष के बढ़ता जाएगा। कहना कठिन है कि सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की इस कोशिश का कितना चुनावी लाभ सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिलेगा, मगर इस प्रयास में जो देनदारी बनेगी, उसका बोझ आने वाली सभी सरकारों को उठाना होगा।

पेंशन के रूप में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिले, यह कल्याणकारी सोच है। मगर ऐसी सुरक्षा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को क्यों मिलनी चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को एक अलग सुविधा-प्राप्त वर्ग के रूप में रखने के प्रयासों के दुष्परिणाम पहले सामने आ चुके हैं। उसका समाधान नई पेंशन व्यवस्था से ढूंढा गया था। तमिलनाडु सरकार (इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं), उस व्यवस्था को पलटने जा रही है। चुनाव से ठीक पहले ऐसा कदम समस्याग्रस्त है। बेहतर नजरिया यह होता कि समाज के सभी तबकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में कदम उठाया जाता। आखिर सरकारी कर्मचारी भी समाज की ही हिस्सा हैं। उन्हें अलग वर्ग में रखकर राजनीतिक दल खराब मिसाल पेश कर रहे हैं।

ब्लॉग

वेनेज़ुएला संकट: अमेरिकी निरंकुशता और वैश्विक कानूनों का हनन

ललित गर्ग

वेनेज़ुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में नियम-कानूनों से संचालित होती है या फिर ताकतवर राष्ट्रों की इच्छा ही वैश्विक न्याय का नया मानदंड बन चुकी है। निश्चित तौर पर वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमला महाशक्तियों की निरंकुशता को दर्शा ही रहा है, यह वैश्विक कानूनों का अतिक्रमण भी है, जो अमेरिकी दादागिरी का त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण संकेत है, वह केवल लैटिन अमेरिका तक सीमित घटना नहीं है, बल्कि समूची दुनिया के लिये एक खतरनाक मिसाल है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेज़ुएला में सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, उससे जुड़े कूटनीतिक, राजनीतिक और अन्तराष्ट्रीय कानून संबंधी सवाल जो खडे. हुए ही हैं, पर अमेरिका को हस्तक्षेप का अवसर देने के लिये मादुरो की नीतियां भी चर्चा में आई हैं। वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले की वजहें हो सकती है, लेकिन ट्रंप को यह तो सुनिश्चित करना ही होगा कि यह राष्ट्र अस्थिरता का अड्डा न बन जाये।

अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को वैश्विक शांति का मसीहा घोषित करते नहीं थकते, लेकिन उनकी नीतियां और कार्रवाइयाँ बार-बार युद्ध, हस्तक्षेप और सत्ता परिवर्तन की मानसिकता को उजागर करती हैं। यह वही अमेरिका है जो एक ओर लोकतंत्र, मानवाधिकार और संप्रभुता की दुहाई देता है, तो दूसरी ओर एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का दुर्लभ उदाहरण है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वाशिंगटन इस लैटिन अमेरिकी देश का संचालन करेगा। यह एक खतरनाक परंपरा है, जिसकी पुनरावृत्ति अमेरिकी महाद्वीप से बाहर होने की आशंका भी बलवती हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि निकोलस मादुरो के पतन के बाद वेनेज़ुएला में मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से मादुरो को लगातार खलनायक बनाने की कोशिशों में एक वैश्विक तंत्र लगा हुआ था। इस तरह की दोहरी नीतियां केवल विडंबनापूर्ण नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के लिये घातक है। वेनेज़ुएला संकट को केवल मादुरो बनाम अमेरिका के टकराव के रूप में देखना वास्तविकता को सरलीकृत करना होगा। इसमें संदेह नहीं कि मादुरो सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, दमनकारी नीतियों, चुनावी अनियमितताओं और मानवाधिकार हनन जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। लाखों वेनेज़ुएलावासी देश छोड़ने को मजबूर हुए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जनता त्रस्त हुई। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि किसी देश की आंतरिक विफलताओं को आधार बनाकर बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को वैध ठहराना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आत्मा के विरुद्ध है। यदि यही मापदंड हो, तो दुनिया के अनेक देशों में बाहरी हस्तक्षेप का अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है।

दरअसल, वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि वेनेज़ुएला के मामले में अमेरिका की असली चिंता न लोकतंत्र है और न ही मानवाधिकार, बल्कि वहां के विशाल तेल भंडार हैं। वेनेज़ुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा देश है और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की अमेरिकी भूख कोई नई बात नहीं है। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान इसके उदाहरण हैं, जहां 'लोकतंत्र स्थापना' के नाम पर हस्तक्षेप हुआ, लेकिन परिणामस्वरूप अस्थिरता, गृहयुद्ध और मानवीय संकट ही पैदा हुआ। ट्रंप का यह बयान कि मादुरो को पकड़ने के अभियान का खर्च वेनेज़ुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, इस पूरे घटनाक्रम की मंशा को बेनकाब करता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि यह कार्रवाई न्याय या नैतिकता से नहीं, बल्कि संसाधनों पर नियंत्रण की साम्राज्यवादी सोच से प्रेरित है। किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इस तरह दावा करना उपनिवेशवादी मानसिकता का आधुनिक संस्करण है। इस अमेरिकी कार्रवाई के भू-राजनीतिक परिणाम भी गहरे और दूरगामी होंगे। रूस और चीन ने इसे नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिये गंभीर खतरा बताया है। मादुरो के आलोचक रहे कुछ अमेरिकी सहयोगी देश भी अब खुलकर चिंता जता रहे हैं। यह संकट वैश्विक ध्रूवीकरण को और तेज कर सकता है। विशेष रूप से चीन को इस घटनाक्रम से अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं, विशेषकर ताइवान पर अमेरिकी आलोचना को कमजोर करने का अवसर मिल सकता है। यदि अमेरिका स्वयं संप्रभुता का उल्लंघन करता है, तो वह दूसरों को किस नैतिक आधार पर संयम की सलाह देगा? वेनेज़ुएला संकट का एक और चिंताजनक पहलू वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है। तेल उत्पादन और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। तेल कीमतों में उछाल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर सकता है, विशेषकर विकासशील देशों को। भारत जैसे देशों के लिये यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, जहां ऊर्जा आयात पर निर्भरता अधिक है। यही कारण है कि भारत ने इस घटनाक्रम पर संतुलित रुख अपनाते हुए चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से संवाद व कूटनीतिक समाधान की वकालत की है।

भारत का यह दृष्टिकोण न केवल व्यावहारिक है, बल्कि नैतिक रूप से भी अधिक जिम्मेदार है। युद्ध और हस्तक्षेप किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है कि इराक और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका को अंततः अपमानजनक विदाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वे देश आज भी स्थिरता और शांति से कोसों दूर हैं। युद्ध शुरू करना भले आसान हो, लेकिन शांति और सुशासन स्थापित करना अत्यंत कठिन होता है-यह सत्य अमेरिका बार-बार भूलता रहा है। ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह स्वयं को शांति का अग्रदूत बताता है, लेकिन उसकी हर बड़ी विदेश नीति पहल टकराव और दबाव की राजनीति पर आधारित दिखती है। यह दोहरी मानसिकता न केवल अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की प्रासंगिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। यदि शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों के अनुसार नियम तोड़ने लगें, तो वैश्विक व्यवस्था अराजकता की ओर बढ़ेगी।

वेनेज़ुएला का संकट पूरी दुनिया के लिये एक चेतावनी है। यह बताता है कि आज भी शक्ति-राजनीति मानवता, शांति और कानून से ऊपर रखी जा रही है। जरूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर इस तरह के एकतरफा हस्तक्षेपों का विरोध करे और संवाद, कूटनीति तथा बहुपक्षीय समाधान को प्राथमिकता दे। किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन का निर्णय वहां की जनता को करना चाहिए, न कि विदेशी सेनाओं को। अंततः, अमेरिका को यह समझना होगा कि किसी 'निरंकुश शासक' को हटाना शायद सैन्य शक्ति से संभव हो जाए, लेकिन किसी देश को स्थायी शांति, स्थिरता और समृद्धि देना केवल टैंकों और बमों से नहीं हो सकता। इसके लिये धैर्य, संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान आवश्यक है। यदि अमेरिका वास्तव में वैश्विक शांति का पक्षधर है, तो उसे अपनी दोहरी नीति त्यागनी होगी। अन्यथा, वेनेज़ुएला जैसी घटनाएँ बार-बार दोहराई जाएंगी और दुनिया एक और अस्थिर, असुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ती जाएगी।

कानपुर गैंगरेप केस: 'मैं निर्दोष हूं, सीबीआई जांच करा लें'... आरोपी दारोगा अमित मौर्या ने पुलिस कमिश्नर और सीएम को लिखा लेटर

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सचेंडी थाना क्षेत्र में बीते 5 तारीख की रात गैंगरेप की घटना में आरोपी दारोगा अमित मौर्या ने सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी करते हुए सफाई पेश की है। आरोपी दारोगा ने पत्र को मुख्यमंत्री और कानपुर पुलिस कमिश्नर को संबोधित करते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। 50000 के इनामी फरार दारोगा अमित मौर्या ने अपने आपको निर्दोष बताते हुए पत्र में कई बातें लिखी हैं। फिलहाल घटना के 7 दिन बाद फरार दारोगा को पुलिस नहीं ढूंढ पाई है।

दारोगा अमित मौर्या द्वारा बनाया गया एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें अमित मौर्या गैंगरेप पीड़िता और उसके भाई व आरोपी शिवबरन को चौकी में खड़ा करके बातचीत कर रहा है, जो कि घटना के अगले दिन का बताया

जा रहा है। इस वीडियों में पीड़िता आरोपी दारोगा अमित मौर्या को पहचान नहीं पा रही थी। अमित ने ये वीडियो अधिकारियों को भेजते हुए अपनी सफाई पेश की।

सीबीआई जांच की मांग की

कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के चर्चित सचेंडी गैंगरेप मामले में नामजद दारोगा अमित मौर्या ने अपने आपको निर्दोष बताने के लिए नया पैंतरा अपनाया है। उसने खुद को पाक साफ बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। दारोगा अमित कुमार मौर्य ने पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पत्र लिख न्याय की गुहार गुहार लगाई। सीबीआई जांच कराकर षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दारोगा अमित मौर्या ने बताया कि RPF प्रभारी के मिली सूचना पर जांच करने के लिए भीमसेन भेजा गया था।

RPF टीम ने पकड़ा था चोरी का तेल

अपने लेटर में दारोगा अमित मौर्या ने बताया कि RPF टीम द्वारा चोरी का तेल पकड़ा गया था। तेल चोरी करने वाले आरोपी फरार हो गए थे। उनकी जानकारी के लिए मैं जांच करने भीमसेन पहुंचा था। रात करीब 9:00 बजे आरपीएफ प्रभारी आए और उनसे बातचीत कर जानकारी ली, जिसके CCTV फुटेज उपलब्ध हैं। शिवबरन का पूर्व में डीजल चोरी में नाम उजागर हुआ था, जिसके बाद दारोगा अमित मौर्य द्वारा उसे भीमसेन बुलाया गया था।

शिवबरन अपनी बाइक से मौके पर पहुंचा था। शिवबरन से पूछताछ के दौरान RPF प्रभारी निरीक्षक की किसी से फोन पर बातचीत चल रही थी, लेकिन शिवबरन को संदेह हुआ कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। इस पर शिवबरन को बताया गया कि पर्सनल कॉल चल रहा है। सुबह पता चला जो लड़का रात में मिला था, वह रेप का आरोप लगा रहा है। जानकारी होने पर मेरे द्वारा पूरी जानकारी थाना प्रभारी सचेंडी दी को दी गई।

आरपीएफ प्रभारी का बयान दर्ज कराएं

मुकदमा वादी व पीड़िता को चौकी बुलाया गया, जो लगातार किसी सुधीर नाम के व्यक्ति से बात कर रहे थे। इसी की रिकॉर्डिंग दारोगा अमित मौर्य द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। दारोगा अमित मौर्य ने पूरी घटना की जानकारी के लिए उच्च अधिकारियों से आग्रह कर आरपीएफ प्रभारी का बयान लेने को कहा।

स्थापना दिवस पर बच्चों को सम्मानित किया

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट परिवार द्वारा स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन नगर के एक होटल में दीप प्रज्वलित कर किया गया, अतिथि के रूप में ओलम्पियन अर्जुन अवार्डी हॉकी के पूर्व खिलाडी अशोक ध्यानचंद, विशिष्ट अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्या, और भाजपा जिला अध्यक्ष अजित प्रजापति, रहे । जिले के हॉकी खिलाडी बच्चे , महिला सुरक्षा सम्मान, शिक्षक सम्मान, चिकित्सा सम्मान, सामाजिक संस्था सम्मान, ट्रस्ट परिवार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस ट्रस्ट के माध्यम से दूसरी बार जौनपुर में आने को मिला, जिस तरह से संस्था समाज में जुड के कार्य कर रहीं हैं यह एक मिशाल ही है,प्रशांत सिंह ने कहा कि आज समाज के हर वर्ग से जुडकर कार्य कर रही है,चाहे शिक्षक, चिकित्सक, समाजसेवी संस्था के साथ किन्नर समाज को भी मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है,। कार्यक्रम में डॉ पी के सिंह, डॉ तेज सिंह, डॉ विजय कुमार सिंह, शशिकांत सिंह,अखिलेशवर शुक्ला, डॉ अरुण त्रिपाठी, जितेन्द्र यादव, राधिका सिंह, नागेंद्र सिंह, कंचन सिंह, कनक सिंह, दीपक श्रीवास्तव, नीलम मिश्रा रेनू अग्रहरी, दीपक सिंह मंटो, आदि उपस्थित रहे। संचालन दीपक सिंह चंदेल ने किया।

विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षा भवन में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर राम आसरे सिंह ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद को युवाओं के लिए पथप्रदर्शक बताते हुए कहा कि आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रसेवा ही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे विवेकानंद के विचारों को जीवन में आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। विशिष्ट अतिथि शिखा श्रीवास्तव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि आज का युवा सकारात्मक सोच, अनुशासन और कर्मठता को अपनाए, तो वह समाज और देश को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के अमर संदेश "उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत" को वर्तमान समय में

अत्यंत प्रासंगिक बताया।कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुधांशु सिन्हा ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा सभी आगंतुक शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का औपचारिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज के वैश्विक परिवेश में व्याप्त अशांति और संघर्ष के समाधान के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। डॉ. प्रशांत कुमार पाण्डेय ने स्वामी विवेकानंद को युवाओं का सच्चा रोल मॉडल बताते हुए कहा कि उनके आदर्शों का अनुसरण कर युवा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रोफेसर रीता सिंह ने कहा कि विवेकानंद ने शिक्षा को भारतीय चिंतन से जोड़ते हुए उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया। प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, डॉ. गीता सिंह, डॉ. सुलेखा सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक, दार्शनिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। डॉ संतोष सिंह, डॉक्टर डी0के सिंह, डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव, डॉ0 निधि सिंह एवं चंद्र प्रकाश गिरी उपस्थित रहे।

दुर्घटना वाले टेलर को पुलिस ने चालक सहित पकड़ा

जौनपुर। जलालपुर क्षेत्र के रेहटी गेट के पास तीन जनवरी की सड़क घटना वाले टेलर को पुलिस ने सोमवार को चालक सहित पकड़ लिया।चालक से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है।ज्ञात हो तीन जनवरी वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र रघुनाथपुर गांव निवासी विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय सुक्खन राम घर से जौनपुर की तरफ जा रहे थे।ऊक्त गेट के सामने खड़े टेलर से पीछे से आकर टकरा गए।जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी थी।घटना के बाद टेलर चालक टेलर लेकर फरार हो गया था।पुलिस ने सीसी कैमरे के फुटेज से टेलर का नम्बर निकाला।उसके बाद पुलिस की टीम ऊक्त टेलर की तलाश में थी।सोमवार को हौज टोलप्लाजा के पास एसआई विजय कुमार व गोविंद शाह की टीम ने टेलर को चालक सहित पकड़ लिया।थानाप्रभारी गजानन्द चौबे ने बताया कि घटना के बाद से ही टीम बनाकर टेलर की तलाश की जा रही थी।

हरदोई शूटआउट : थाने के अंदर किया पत्नी का कत्ल, प्रेमी संग भागने से नाराज था पति, सरेआम मारी गोली

आर्यावर्त संवाददाता

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेमी के साथ फरार हुई पत्नी की पति ने थाने के भीतर ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात ने न केवल इलाके में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना हरदोई के पाली थाना क्षेत्र की है। रामापुर अटरिया निवासी अनूप की शादी 17 साल पहले सोनी के साथ हुई थी। बीते 7 जनवरी को सोनी अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी सुरजीत (निवासी शाहजहांपुर) के साथ फरार हो गई थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कल ही महिला को बरामद किया था और वह पुलिस अभिरक्षा में पाली थाने में मौजूद थी।

आज सुबह जब सोनी खाना लेने के लिए थाने की कैंटीन की ओर जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे

पति अनूप ने अवैध असलहे से उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से सोनी लहूलुहान होकर गिर पड़ी। उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस हिरासत में वारदात से उठे सवाल

थाने जैसे सुरक्षित स्थान पर अवैध हथियार लेकर घुसना और पुलिस की मौजूदगी में हत्या करना, सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। घटना के बाद थाने के बाहर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही जिले के आला पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

आरोपी पति गिरफ्तार, पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज

पुलिस ने आरोपी पति अनूप को वारदात के तुरंत बाद असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि वह पत्नी की बेवफाई से तंग था और बदला लेना चाहता था।

हरदोई के पुलिस अधीक्षक (SP) अशोक कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि थाने के भीतर हुई इस सुरक्षा चूक को गंभीरता से लिया गया है। पुलिसकर्मियों की लापरवाही को देखते हुए उनके विरुद्ध कड़ी विभागीय और विधिक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

पति की हत्या के बाद अपनी ही बात उलझी पत्नी, उठा ले गई बरेली पुलिस... करीबी पर शक

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सिरौली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले भूड़ा गांव में एक युवक की सोते समय धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुरेश पाल सिंह यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है।

रविवार रात की इस घटना में पुलिस को शक है कि हत्यारा कोई करीबी हो सकता है। इसी शक के चलते पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक हत्या की असली वजह सामने नहीं आ सकी है।

चारपाई पर खून से लथपथ मिला शव

दरअसल, गांव भूड़ा निवासी सुरेश पाल सिंह यादव रविवार रात अपने घर में सो रहे थे। रात करीब 10:30 बजे गांव के कुछ लोगों ने उनके भाई चंद्रपाल को सूचना दी कि सुरेश की हालत ठीक नहीं है। जब चंद्रपाल घर पहुंचे तो देखा कि सुरेश चारपाई पर खून से लथपथ पड़े थे। शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई वार के निशान थे।

घटना के समय घर में ही सुरेश की पत्नी ममता मौजूद थी। वह चारपाई के पास बैठी रो रही थी। चंद्रपाल ने जब उससे घटना के बारे में पूछा तो उसने कोई साफ जवाब नहीं दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही सिरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने घर और आसपास का मुआयना किया। मौके से कोई साफ सुराग नहीं मिला, लेकिन हत्या का तरीका देखकर पुलिस को शक हुआ कि हमलावर कोई जान-पहचान का ही व्यक्ति हो सकता है।

पत्नी से पूछताछ, पुलिस हिरासत में

पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मृतक की पत्नी ममता से पूछताछ शुरू की। पुलिस के अनुसार ममता से कई बिंदुओं पर सवाल किए गए, लेकिन वह किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। उसके बयानों में लगातार विरोधाभास देखा गया।

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ममता चार दिन पहले ही अपने मायके बिहार से गांव लौटी थी। इसी वजह से पुलिस का शक और गहरा गया। फिलहाल पत्नी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा।

परिवार के अन्य सदस्यों और गांव वालों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद खुलेगा राज

पुलिस ने शव को रात में ही पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया था। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि हत्या के पीछे क्या कारण है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के समय और हमले के तरीके को लेकर कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी।

शोध और नवाचार नीति का लाभ उठाएं शिक्षक : कुलपति

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ने शिक्षकों में शोध, नवाचार एवं अकादमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शोध प्रोत्साहन एवं उत्कृष्टता पुरस्कार नीति को लागू कर दिया है। सोमवार को कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि इस नीति का शिक्षक अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा यह प्रोत्साहन नीति शिक्षकों को शोध और नवाचार के लिए प्रेरित करेगी ।यह नीति विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) द्वारा तैयार की गई है।कुलपति ने कहा कि इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्यों, अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन, पेटेंट प्राप्ति तथा बाह्य वित्त पोषित शोध परियोजनाओं को बढावा देना है।उन्होंने कहा कि इस नीति के

अंतर्गत विश्वविद्यालय के नियमित एवं संविदा शिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं में शोधपत्र प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति शिक्षक अधिकतम 5,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जिसमें पंजीकरण शुल्क तथा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल यात्रा किराया सम्मिलित होगा। कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर गिरिधर मिश्र ने कहा कि उच्च प्रभाव वाले शोध प्रकाशनों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय ने प्रभाव कारक (इम्पैक्ट फैक्टर) के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन की व्यवस्था किया है। एससीआई एवं स्कोपस जैसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधपत्रों पर 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वहीं, एक वर्ष में कुल इम्पैक्ट फैक्टर 20 या उससे अधिक होने पर संबंधित शिक्षक को "शोध उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया जाएगा।

तनाव में ड्यूटी, हेल्थ मॉनिटरिंग तक नहीं... गश्त के बाद कमरे में मिला यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर का शव, क्या है मौत की वजह?

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस विभाग को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जारचा थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर संजय यादव की मौत ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अत्यधिक काम के दबाव और समय पर स्वास्थ्य की जांच न होने के चलते एक सब-इंस्पेक्टर की जान चली गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सब-इंस्पेक्टर की मौत ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के कारण हुई।

यह घटना सिर्फ एक पुलिसकर्मी की असमय मौत नहीं, बल्कि उस सिस्टम की सच्चाई है, जिसमें वर्दीधारी जवान बिना आराम, बिना नियमित स्वास्थ्य जांच और लगातार मानसिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक,

सब-इंस्पेक्टर संजय यादव घटना वाली रात नियमित गश्त ड्यूटी पर थे। रात करीब 11 बजे वह गश्त पूरी कर थाने लौटे थे। उस समय उन्होंने सहयोगी पुलिसकर्मियों से हल्के सीने में दर्द की शिकायत भी की थी।

इसके बाद उन्होंने दवा ली और अपने कमरे में आराम करने चले गए। रात में ठंड भी अधिक थी और लंबे समय से लगातार ड्यूटी के कारण वह पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए बताए जा रहे थे। लेकिन सुबह जब काफी देर तक वह बाहर नहीं निकले और फोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला, तब साथी पुलिसकर्मियों को चिंता हुई।

दरवाजा तोड़ा गया, अंदर मिला शव

काफी देर तक संपर्क न होने पर दो पुलिसकर्मी उनके कमरे के बाहर पहुंचे। अंदर से दरवाजा बंद था और कोई हलचल नहीं थी। संदेह होने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां सब-इंस्पेक्टर संजय यादव कमरे के अंदर बेड पर अचेत अवस्था में पड़े मिले। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचित किया गया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सब-इंस्पेक्टर की मौत ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के कारण हुई है। डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक तनाव, ठंड, लगातार ड्यूटी और समय पर स्वास्थ्य जांच न होना इस तरह की मौतों के बड़े कारण बनते जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले में किसी तरह की संदिग्ध परिस्थिति या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं।

> **क्या बोले डीसीपी?**
>
> डीसीपी पुलिस लाइन शैलेंद्र कुमार ने बताया कि हर सप्ताह रविवार को पुलिसकर्मियों की नियमित जांच की जाती है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल की मदद से हर माह पुलिस लाइन में सिविल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाता है। समय-समय पर पुलिसकर्मियों को निर्देशित भी किया जाता है कि वे अपनी समय पर जांच कराएं, लेकिन फिर भी कुछ पुलिसकर्मी लापरवाही बरतते हैं। रहा सवाल छुट्टियों का, साल में 30 दिन और आमतौर पर 15 दिन का अवकाश दिया जाता है, जो त्योहारों और व्यक्तिगत कार्यों के लिए होता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश और अन्य विशेष परिस्थितियों में अवकाश भी मिलता है, जो नियमों के अनुसार होता है।

खुशी का माहौल बदला मातम में

सब-इंस्पेक्टर संजय यादव के परिवार में कुछ दिन पहले ही खुशी का माहौल था। करीब एक सप्ताह पहले उनके बड़े बेटे की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। इस खुशी में संजय यादव ने पूरे थाने में मिठाई बांटी थी। वह परिवार और साथियों के बीच खुशमिजाज और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। उनके परिवार में दो बेटे हैं। बड़ा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा है, जबकि छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। अचानक हुई इस मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य पर बड़ा सवाल

इस घटना के बाद पुलिस विभाग में काम के दबाव और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। विभाग के कई पुलिसकर्मियों का कहना है कि न तो उन्हें नियमित वीकली ऑफ मिल पाता है और न ही समय-समय पर हेल्थ चेकअप की कोई ठोस व्यवस्था है। लगातार ड्यूटी, सुबह-शाम गश्त, मानसिक तनाव, फील्ड में काम का दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच पुलिसकर्मी खुद की सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसका नतीजा ऐसी दर्दनाक घटनाओं के रूप में सामने आता है।

तनाव बना साइलेंट किलर?

कार्डियोलॉजी डॉ तुषार अग्रवाल सीनियर डॉ सर्वोदय हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा का कहना है कि ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के मामलों में मानसिक तनाव एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। अगर समय पर आराम, नियमित मेडिकल जांच और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए, तो ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

सब-इंस्पेक्टर की मौत के बाद पुलिसकर्मियों और उनके संगठनों की ओर से मांग उठ रही है कि पुलिसकर्मियों को नियमित वीकली ऑफ दिया जाए, समय-समय पर अनिवार्य हेल्थ चेकअप कराया जाए और अत्यधिक ड्यूटी के दबाव को कम करने के लिए स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह अपने बेटे, पति या पिता को न खोना पड़े।

इतिहास के पन्नों से पहाड़ों की वादियों तक...एक बार अकेले जरूर घूमें भारत की ये 5 जगहें

घूमने की बात आए तो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर से लेकर मॉर्डन कल्चर और प्राकृतिक जगहों तक भारत में ही इतनी खूबसूरती भरी पड़ी है कि आप बस वहीं रह जाना चाहेंगे। इस आर्टिकल में जानेंगे देश की ऐसी 5 जगहों के बारे में जहां आपको जिंदगी में एक बार अकेले जरूर जाना चाहिए।

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में कई संस्कृतियां एक साथ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा हमारे देश की भौगोलिक स्थिति में भी कमाल की वर्सेटिलिटी है। फिर चाहे वो ओल्ड कल्चर हो या फिर हिस्टोरिकल इमारतें और प्राकृतिक खूबसूरती। आप पहाड़ों की सैर कर सकते हैं, नदियों के किनारे शांति से समय बिता सकते हैं और समुद्र तटों पर शोर से दुर प्रकृति का संगीत सुन सकते हैं। आप भी अगर उन लोगों में से हैं जो भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो जान लें भारत की उन 5 जगहों के बारे में जो आपके लिए परफेक्ट हैं।

इस आर्टिकल में हमनें वो जगह बताई हैं जहां पर आप एकांत तटों पर शांति के साथ सुकून महसूस करने के अलावा एडवेंचर कर सकते हैं। पहाड़ियों में प्रकृति को निहार सकते हैं और अगर इतिहास के साथ अध्यात्म में दिलचस्पी है तो पुराने मंदिरों, खंडहरों में छिपी हिस्ट्री को खंगालने से लेकर ध्यान योग तक बहुत कुछ कर सकते हैं और खुद में एक नई एनर्जी का फ्लो महसूस कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन जगहों के बारे में।

योग नगरी ऋषिकेश, उत्तराखंड

उत्तराखंड के ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। गंगा के किनारे बसी ये जगह खुद को खोजने यानी आत्म विश्लेषण करने के लिए एक बेहतरीन प्लेस है। यहां पर आप योगा, ध्यान करने के साथ ही और आध्यात्मिक रिट्रीट्स का अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा ये एडवेंचर पसंद लोगों के लिए भी बेस्ट पॉइंट है। यहां पर वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, नेचर वॉक, जैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आप प्रकृति के बीच अकेले वक्त बिता सकते हैं। इसके अलावा ये जगह काफी फ्रेंडली है। आपको ऑफ सीजन में सस्ते आश्रम से लेकर ठहरने के लिए हॉस्टल मिल जाएंगे साथ ही खाने की भी लग्जरी से लेकर बजट फ्रेंडली जगहें यहां पर मिल जाती हैं।

यूनेस्को धरोहर हम्पी, कर्नाटक

अगर आपको इंडियन हिस्ट्री, के साथ वास्तुकला में दिलचस्पी है तो हम्पी आपके लिए बेस्ट जगह है। यह एक बहुत ही बड़ा ओपन-एयर म्यूजियम जैसा लगता है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है क्योंकि हम्पी अपने प्राचीन मंदिरों, विशाल चट्टानों और नदी के शानदार व्यू के लिए जाना जाता है। यहां बाइकिंग करने से लेकर, सूर्यास्त के समय खंडहरों को देखना और लोकल कैफे में बैठकर अपनी मनपसंद खाने को एक्सप्लोर करना कमाल का अनुभव रहेगा। यहं पर आपको एडवेंचर से लेकर फोटोग्राफी तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा।ये एक्टर अक्षय कुमार की पसंदीदा जगहों में से एक है।

बनारस को करें एक्सप्लोर

भगवान शिव की नगरी वाराणसी, बनारस या कहें कि काशी।।ये एक ऐसी जगह है जो कई बड़े सेलिब्रिटी की भी पसंदीदा है। न सिर्फ यहां का लोकल फूड दुनियाभर में मशहूर है, बल्कि और भी बहुत कुछ है बनारस में एक्सप्लोर करने को। खासतौर पर यहां की संकरी गलियां टूरिस्ट को काफी पसंद आती हैं, क्योंकि यहीं देखने को मिलता है ठेठ बनारसी कल्चर। इस जगह के ऊपर न जाने कितनी कहानियां, कविताएं तक लिखी गई हैं। कहा जाता है कि बनारस आएं तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कम से कम 3-4 दिन की फुर्सत के साथ आना चाहिए। यहां शाम को गंगा घाट पर अकेले बैठकर वक्त बिताना सबसे सुकून भरे पलों में से एक रहेगा।

एक्सप्लोर करें माजुली द्वीप,असम

अगर आप भीड़-भाड़ से दूर और संस्कृति और नेचुरल ब्यूटी से भरपूर जगह पर जाना चाहते हैं, तो माजुली जाना चाहिए। असम में बसी ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहां पर आप को कमाल की हरियाली देखने को मिलेगी जो पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। इसके अलावा असमिया कल्चर, यहां की कला और शांति आपको आत्मिक एक्सपीरियंस से भर देंगे। आप यहां पर बोटिंग कर सकते हैं, मठों को विजिट कर सकते हैं और गांवों में जाना तो आपके लिए बहुत ही कमाल का अनुभव रहेगा।

वर्कला बीच, केरल

आपको पहाड़ नहीं बल्कि समुद्र पसंद है तो आपको कर्नाटक के वर्कला जाना चाहिए।वर्कला क्लिफ बीच पर सूर्यास्त का नजारा कमाल का लगता है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे और कैमरे में कैद कर लेना चाहेंगे, क्योंकि चट्टानों के बीच से डूबता हुआ सूर्य कमाल का दृश्य होता है। आयुर्वेदिक उपचार ट्रीटमेंट कराने से लेकर योग सीखने तक जैसी एक्टिविटी होती हैं जो आपकी जर्नी को और भी खास बना देंगी। इसके अलावा गोवा या कुछ बाकी बिजी बीच की तुलना में ये जगह बहुत ही शांत और सुकून भरा एक्सपीरियंस देती है।

पुरुषों को बार-बार यूरिन आना हो सकता है इस कैंसर का लक्षण?

पुरुषों को बार-बार यूरिन आने की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रोस्टेट कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है।

कई पुरुषों को पेशाब बार-बार आने की शिकायत रहती है। कई बार इसे उम्र बढ़ने या सामान्य यूरिन संबंधी समस्याओं से जोड़ दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी यह प्रोस्टेट कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में सबसे आम कैंसर में से एक है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि में विकसित होता है। यह ग्रंथि ब्लैडर के नीचे और पेल्विस में स्थित होती है और पुरुषों के हॉर्मोन और रीप्रोडक्टिव स्वास्थ्य से जुड़ी होती है।

शुरुआती स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर अक्सर लक्षण नहीं दिखाता, इसलिए बार-बार यूरिन आना या यूरिन के बहाव में बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। समय पर जांच और पहचान से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि पुरुषों को बार-बार यूरिन आना क्या प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण है और यह कैंसर क्यों होता है।

क्या बार-बार यूरिन आना प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण है?

मैक्स हॉस्पिटल में ऑनकोलॉजिस्ट डॉ। रोहित कपूर बताते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती दौर में बार-बार यूरिन आना आम लक्षण हो सकता है। इसके अलावा पेशाब करने में तकलीफ, बहाव कमजोर होना, रात में बार-बार उठना, अचानक पेशाब रोकने में कठिनाई और पेशाब में खून आना भी संकेत हो सकते हैं।

कुछ पुरुषों में पीठ, हिप या रीढ़ में दर्द, थकान और वजन घटने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। शुरुआती स्टेज में लक्षण हल्के होते हैं, इसलिए पुरुष अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। समय पर प्रोस्टेट जांच और PSA टेस्ट करवाना जरूरी है ताकि कैंसर की पहचान जल्दी हो और इलाज प्रभावी बने।

प्रोस्टेट कैंसर के क्या कारण हैं?

प्रोस्टेट कैंसर के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ना सबसे सामान्य कारण है, 50 साल से ऊपर पुरुषों में जोखिम ज्यादा होता है। परिवार में प्रोस्टेट कैंसर का इतिहास भी खतरे को बढ़ाता है। हॉर्मोनल बदलाव, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन की उच्च मात्रा कैंसर की संभावना बढ़ा सकती है।

साथ ही, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे अधिक फैट वाला भोजन, कम फाइबर का सेवन, धूम्रपान और शराब का सेवन भी जोखिम बढ़ाते हैं। इन सभी कारणों से प्रोस्टेट सेल्स में असामान्य बढ़ोतरी हो सकती है और धीरे-धीरे कैंसर विकसित हो सकता है।

कैसे करें बचाव?

संतुलित और पोषक डाइट लें, हरी सब्जियां और फाइबर शामिल करें।

नियमित रूप से एक्सरसाइज और वॉक करें।

धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं।

50 साल के बाद नियमित प्रोस्टेट जांच और PSA टेस्ट कराएं।

पेशाब संबंधी लक्षण दिखते ही डॉक्टर से तुरंत सलाह लें।

रिपब्लिक डे के लॉन्ग वीकेंड पर जाना है वाघा बॉर्डर, ट्रिप की हर डिटेल जानें

इस बार देश 77वां रिपब्लिक डे मनाएगा। 77वां गणतंत्र दिवस और भी खास होने वाला है। क्योंकि इस बार 26 जनवरी पर लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है। ऐसे में आपके लिए घूमने का बेस्ट मौका है। चलिए आपको बताते हैं देश की एक ऐसी जगह, जहां आप 3 दिन की ट्रिप प्लान कर देशभक्ति जगा सकते हैं।

रिपब्लिक डे इस बार घूमने का शानदार मौका लेकर आ रहा है। देशभक्ति के इस खास अवसर पर 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है। दरअसल, 26 जनवरी 2026 को सोमवार होने के कारण लोगों को 3 दिन की लंबी छुट्टी मिल रही है। ऐसे में रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेकर अगर आप कहीं जाने का मन बना रहे हैं, तो यह समय बिल्कुल परफेक्ट है। गणतंत्र दिवस का माहौल अपने आप में जोश, गर्व और बलिदान की याद दिलाता है, और अगर इस दिन को किसी ऐतिहासिक या देशभक्ति से जुड़ी जगह पर बिताया जाए, तो एक्सपीरियंस और भी यादगार बन जाता है।

आज इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसी देशभक्ति वाली जगह बताने जा रहे हैं, जहां आप अपनी 3 दिन की छुट्टी बिता सकते हैं। यहां आकर आपको देशभक्ति या एहसास होगा और वीरसपुतों के बलिदान की भी याद दिलाएगी।

रिपब्लिक डे के लॉन्ग वीकेंड पर घूम आएं ये जगह

हम बात कर रहे हैं, वाघा बॉर्डर की...।रिपब्लिक डे पर पड़ रही 3 दिन की छुट्टी में घूमने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। दिल्ली से इसकी दूरी भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में आप 3 दिन यहां आराम से बिता सकते हैं। दिल्ली से वाघा बॉर्डर की दूरी 500 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में आपको लगभगल 8 घंटे का समय लग सकता है।

वाघा बॉर्डर बढ़ाएगा देशभक्ति

देशभक्ति के माहौल को जीने के लिए वाघा बॉर्डर बेहतरीन जगह है। ये भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के बीच स्थित है। यहां आकर आपके एक अलग ही एहसास होगा। रिपब्लिक डे पर तो यहां का माहौल देखने लायक होता है। यहां हर शाम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें भारतीय बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स सैनिक झंडा उतारने और परेड के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा तेज मार्चिंग और synchronized कदम भी देखने को मिलता है। आप यहां सैनिकों की परेड भी देख सकते हैं और देशभक्ति का अलग अनुभव ले सकते हैं।

दिल्ली से वाघा बॉर्डर कैसे पहुंचे

दिल्ली से वाघा बॉर्डर (अटारी, पंजाब) पहुंचने के लिए सबसे पहले आप ट्रेन, बस या कार ले सकते हैं। नई दिल्ली से अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन लें और वहां से टैक्सी लेकर वाघा बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। वहीं, बस या कार से सफर करने पर आपको लगभग 450 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा, जो 810 घंटे में पूरा होता है।

वाघा बॉर्डर जाने के लिए जरूरी नियम

अपना ओरिजिनल पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, या पासपोर्ट, जरूर साथ रखें।

अगर आप वाघा बॉर्डर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने है, जो शाम को होती है तो इसके लिए समय पर पहुंचना जरूरी है।

सुरक्षा कारणों से भारी बैग, शार्प ऑब्जेक्ट्स या किसी प्रकार के हथियार ले जाना मना है।

सीमा पार नहीं की जा सकती, केवल भारतीय पक्ष के स्टैंड तक ही जाने की अनुमति है।

भीड़ काफी ज्यादा होती है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

एंट्री के लिए कोई टिकट नहीं लगती है। समय से पहुंचकर आप अपने लिए जगह बना सकते हैं।

वाघा बॉर्डर के पास की इन जगहों को भी करें एक्सप्लोर

वाघा बॉर्डर के अलावा आप उसके आसपास की कुछ और जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे जल महल, जो अमृतसर का एक ऐतिहासिक स्थल है। जलियावाला बाग जाकर वीरसूपतों को याद कर सकते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाना बिल्कुल न भूलें,जो वाघा बॉर्डर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। वहीं, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो, अटारी बॉर्डर मार्केट जा सकते हैं।

रिन्यूएबल एनर्जी के लिए साल रहा बेमिसाल, इस सेक्टर की इतनी बढ़ गई क्षमता

देश के एनर्जी सेक्टर के लिए साल 2025 शानदार रहा है। इस साल क्लीन एनर्जी में देश की क्षमता बढ़ी है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि भारत ने 2025 में अपनी क्लीन एनर्जी यात्रा में एक रिकॉर्ड-तोड़ साल दर्ज किया, जिसमें नॉन-फॉसिल ईंधन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़कर 266.78 GW हो गई। यह 2024 की तुलना में 22.6 प्रतिशत की ग्रोथ है, जब नॉन-फॉसिल कैपेसिटी 217.62 GW थी और इस साल 49.12 GW की नई नॉन-फॉसिल कैपेसिटी जोड़ी गई।

उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी ने इस ग्रोथ को लीड किया, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2024 में 97.86 GW से बढ़कर 2025 में 135.81 GW हो गई, यानी 38.8 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी। विंड एनर्जी कैपेसिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई, जो 48.16 GW से बढ़कर 54.51 GW हो गई, यानी 13.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी। कुल मिलाकर, सोलर और विंड एनर्जी ने इस साल भारत के रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपैंशन को आगे बढ़ाया।

बायोएनर्जी और स्मॉल हाइड्रो का भी रहा दबदबा

अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स ने भी 2025 में कुल ग्रोथ में अच्छा योगदान दिया। बायोएनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 11.61 GW तक पहुंच गई, जिसमें वेस्ट-टू-एनर्जी ऑफ-ग्रिड प्रोजेक्ट्स से 0.55 GW शामिल है, जो क्लीन फ्यूल प्रोडक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट में लगातार प्रोग्रेस दिखाता है।

स्मॉल हाइड्रो कैपेसिटी बढ़कर 5.16 GW हो गई, जो डिसेंट्रलाइज्ड और लोकल एरिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। बड़ी हाइड्रो कैपेसिटी 50.91 GW थी, जिसमें 7,175.6 MW पंप स्टोरेज शामिल है, जो ग्रिड को स्टेबल रखने और रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने में मदद करता है।

पीएम मोदी का जताया आभार

केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि 2025 में मिली रिकॉर्ड ग्रोथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डायरेक्शन, लॉन्ग-टर्म विजन और लगातार इम्प्लीमेंटेशन को दिखाती है। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्रेस एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई और आत्मनिर्भर ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में भारत के रास्ते को और मजबूत करती है, साथ ही 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी के नेशनल टारगेट की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मिनिस्ट्री देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को और तेज करने के लिए राज्यों और सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करती रहेगी।

'रियल एस्टेट से जुड़ी पॉलिसी सुधरे, होम लोन की लागत घटे'

रियल एस्टेट उद्योग बजट 2026 के बजट में सरकार से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होम लोन की लागत को कम करने पर ध्यान देने की मांग कर रहा है। इससे रुके हुए प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। आइए जानते हैं उद्योग ने क्या-क्या सुझाव दिए।

बजट 2026 में सरकार को रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी पॉलिसी पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आवास की मांग को पुनर्जीवित करने और रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उद्योग का कहना है कि बढ़ती हुई जमीनों की कीमतों के साथ ही निर्माण लागत की वजह से महानगरों में आवासीय मांग प्रभावित हो रही है।

रेपो रेट में कटौती से आवासीय बाजार को सहारा मिला

नारेडको महाराष्ट्र की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और नाहर ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन मंजू याज्ञिक ने कहा रियल एस्टेट सेक्टर को बजट 2026 में ऐसे ठोस उपायों की उम्मींद है, जो घर के स्वामित्व को सार्थक रूप से बढ़ावा दे और आवासीय इकोसिस्टम को मजबूत करें। विशेष रूप से पहली बार घर खरीदने वाले और मध्यम आय वर्ग के खरीदार बढ़ती आवासीय कीमतों और होम लोन की लागत से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती ने आवासीय बाजार के लिए सकरात्मक संकेत दिया है और किफायती आवास बाजार की धारणा में सुधार भी हुआ है। ऐसे में बजट के जरिए जरूरी वित्तीय समर्थन देकर इस गति को बढ़ाया जा सकता है।

पहली बार घर खरीदने वालों और मध्यमवर्ग पर हो फोकस

याज्ञिक का कहना है, इस बजट से एक प्रमुख अपेक्षा होम लोन की प्रभावी लागत को कम करने पर नए सिरे से ध्यान देने की है। साथ ही बढ़ी हुई ब्याज सब्सिडी, लंबे ओर अधिक लचीले लोन टेन्योर और पहली बार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहित करने, नीतिगत ब्याज दरों में कटौती से वास्तविक मासिक ईएमआई को राहत में बदलने में मदद कर सकते हैं। खासकर बड़े शहरों में जहां आवास की वहन क्षमता अब भी चुनौती बनी हुई है।

डेवलपर्स पहली बार घर खरीदने वालों के लिए, विशेष रूप से मध्यम आय वर्ग के उन लोगों के लिए, जो वर्तमान में किफायती आवास लाभों के दायरे से बाहर हैं, मजबूत प्रोत्साहन चाहते हैं। मध्यम आय वर्ग की आवास परियोजनाओं में उपयोगकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा 45 लाख रुपये की वहनीय सीमा से ऊपर है और इसलिए उन्हें 1 प्रतिशत जीएसटी और कर प्रोत्साहनों का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने सीमा को बढ़ाकर लगभग 90 लाख रुपये करने, धारा 80EEA के तहत अतिरिक्त ब्याज कटौती को फिर से शुरू करने और डेवलपर्स के लिए ऋण को आसान बनाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार, इन कदमों से संपत्ति की कीमतें और खरीदारों के लिए मासिक ईएमआई दोनों कम हो सकती हैं।

किफायती आवास सीमाओं पर ध्यान देने की मांग

इस क्षेत्र की प्रमुख मांगों में से एक किफायती आवास के लिए निर्धारित 45 लाख रुपये की सीमा में संशोधन करना है , जिसके बारे में डेवलपर्स का कहना है कि यह अब अधिकांश शहरी क्षेत्रों में बाजार की स्थितियों को नहीं दर्शाता है। बजट 2026 के नजदीक आने के साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र सरकार से शहरी आवास की कीमतों की वास्तविकताओं के अनुरूप कर नीतियों के संबंध में स्पष्ट संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। किफायती आवास श्रेणी के लिए मौजूदा 45 लाख रुपये की सीमा और उससे जुड़ा 1 प्रतिशत जीएसटी लाभ अधिकांश विकास क्षेत्रों में भूमि और निर्माण लागत के अनुरूप नहीं है। इसलिए उद्योग मूल्य सीमा को बढ़ाकर 80-90 लाख रुपये करने और निर्माण अनुबंधों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने से रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है और आवास की नई आपूर्ति को बढ़ाने की मांग कर रहा है।

स्क्वायर याड्र्स के संस्थापक और सीईओ तनुज शोरी कहते हैं कि 2026 के आम बजट से मध्यम आय वाले घर खरीदारों के लिए अधिक कर छूट, उच्च ब्याज कटौती सीमा और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेशक के जरिए किफायती घरों को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है। रियल एस्टेट के लिए नीतिगत समर्थन की अपेक्षा हम इस बजट में कर रहे हैं, जो किफायती और मिड मार्केट में सप्लाई को बढ़ावा दे, क्योंकि हाल के दिनों में अधिकतर ऐसे प्रोजेक्ट पेश किए गए हैं, जो महंगे हैं।

रियल एस्टेट सेक्टर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ देने वाला सेक्टर बनकर उभरा है

अजमेरा ग्रुप के डायरेक्टर, कॉर्पोरेट अफेयर्स धवल अजमेरा कहते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ देने वाला सेक्टर बनकर उभरा है, इसी गति को तेज बनाए रखने के लिए हमें उम्मींद है कि सरकार आगामी बजट में पॉलिसी सुधारों और उपचारात्मक उपायों की घोषणा करेगी। जिससे घर खरीदने वालों और डेवलपर्स दोनों को फायदा होगा। इसके साथ ही सेक्टर को उम्मीद है कि होम लोन की प्रभावी लागत को कम करने पर नए सिरे से ध्यान दे और खरीदारों के दिए जाने वाले ब्याज पर टैक्स बेनिफिट मिले, चाहे लोन कितना भी बड़ा हो। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा और भारतीय रियल एस्टेट इकोसिस्टम पर इसका सकरात्मक असर होगा।

सरकार से इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम शुरू करने की अपील

धवल ने बताया कि भारत को नेट जीरो (इसका लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना है) में बदलने की दिशा में तेजी लाने की जरूरत भी उतनी ही जरूरी है। इस बारे में, हम मंत्रालय से एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम शुरू करने की अपील करते हैं- खासकर ग्रीन-रेटेड रियल एस्टेट डेट के लिए। जबकि डेवलपर्स सस्टेनेबल,आईजीबीसी (भारतीय हरित भवन परिषद) और एलईईडी (ऊर्जा और डिजाइन में नेतृत्व) सर्टिफाइड प्रोजेक्ट बनाने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें पूंजी की अधिक लागत एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। इस एक सुधार उपाय के तौर पर, ग्रीन बॉन्ड पर सरकार की तरफ से 200-300 आधार अंकों की सब्सिडी सीधे तौर पर उधार लेने की लागत को कम कर सकती है, जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स केवल उम्मीदों पर खरे उतरने के बजाय आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

ईरान के विदेश मंत्री का यूएस पर आरोप- प्रदर्शन में हिंसा बहाना, हस्तक्षेप की ताक में डोनाल्ड ट्रंप

तेहरान, एजेंसी। ईरान में बीते 15 दिनों से खामेनई सत्ता के खिलाफ जनता का उग्र विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार विरोधी आंदोलन की आग राजधानी तेहरान से लेकर देश के सभी 31 प्रांतों तक फैल चुकी है। इस बीच अशांत ईरान को लेकर विदेश मंत्री ने बड़ा दावा किया है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का दावा है कि देश के अंदर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है। इसी के साथ उन्होंने हिंसा के लिए इस्राइल और अमेरिका को दोषी ठहराया है। हालांकि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया।

ट्रंप पर लगाया खूनी आंदोलन भड़काने का आरोप

इसी के साथ उन्होंने देश के अंदर उपजे हालात के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी घेरा। अमेरिका पर आरोप लगाते हुए सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को हिंसक और खूनी बनाया गया ताकि ट्रंप को दखल देने का बहाना मिल सके। दरअसल, ट्रंप लगातार ईरान की सरकार को आंदोलनकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर चेतावनी दे रहे हैं।

मृतकों के आंकड़ों पर ईरान की चुप्पी

हालांकि अराघची ने सामने आए मृतकों के आंकड़ों पर कोई बयान या सबूत नहीं दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जिनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी थे। तेहरान में विदेशी राजनयिकों से बात करते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तीखे शब्दों में इस बात पर जोर दिया कि 'स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है'। कतर द्वारा वित्त पोषित अल जजीरा सैटेलाइट न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित बयान में अराघची ने कहा, 'इसीलिए प्रदर्शन हिंसक और खूनी हो गए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल सके। बता दें कि देश के अंदर इंटरनेट बंद होने के बावजूद अल जजीरा को देश के अंदर से लाइव रिपोर्टिंग करने की अनुमति दी गई है।

ईरान में अब तक 544 की मौत

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका की धमकी के बाद ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत करना चाहता है। यह कदम ऐसे समय आया है, जब देशव्यापी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 544 हो गई है। बता दें कि मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विरोध प्रदर्शनों के दौरान 544 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और दर्जनों अन्य मामलों की समीक्षा जारी है। गिरफ्तारी के बाद 10,681 से अधिक व्यक्तियों को जेलों में भेज दिया गया है। देश भर में 186 शहरों में, सभी 31 प्रांतों में 585 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को बिगड़ती आर्थिक स्थिति के विरोध में शुरू हुए थे और तब से सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों में तब्दील हो गए।

ईरान में अब तक क्या-क्या हुआ? बिंदुवार जानिए

ईरान में 28 दिसंबर को महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ।

जिसके बाद 15 दिनों से सरकार के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन जारी है।

अब तक 544 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 10 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी

खामेनई सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही है।

जबकि निर्वासित युवा रेजा पहलवी के समर्थन में लोग आए हैं।

7 जनवरी के बाद ईराक में नए सिरे से आंदोलन तेज हुआ।

इसी दिन पूरे देश में इंटरनेट और टेलीफोन सेना बंद कर दी गई।

ईरान ने मैदान में उतारे 2 करोड़ सैनिक, क्या है बासिज जो अमेरिका से तीसरी बार खामेनेई को बचाएगा

तेहरान, एजेंसी। ईरान की सड़कों पर मचे बवाल को कंट्रोल करने के लिए अयातुल्लाह अली खामेनेई की सरकार ने बासिज नामक अर्द्धसैनिक समूह को मैदान में उतार दिया है। मानवाधिकार आयोग के मुताबिक इस समूह ने ईरान में अब तक 500 दंगाईयों को मौत के घाट उतार दिए हैं। इसे ईरान का सबसे खूंखार सैन्य समूह कहा जाता है। यह एक स्वयंसेवी संस्था है, जो सरकार के खिलाफ आंतरिक बगावत को रोकने के लिए बनाया गया है।

सीएनएन के मुताबिक शुक्रवार (9 जनवरी) को जुमे की नमाज के बाद अली खामेनेई ने देश के नाम एक संबोधन पढ़ा। खामेनेई ने विरोध प्रदर्शन को अमेरिका का एजेंडा बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ईरान किसी के भी सामने नहीं झुकने वाला है। इसके बाद ईरान संसद की सिफारिश पर बासिज समूह को सड़कों पर उतारा गया।

बासिज का मतलब क्या है?

बासिज एक फारसी शब्द है, जिसका मतलब होता है- लामबंदी। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद इसका गठन किया गया था। उस वक्त इस्लामिक क्रांति के नेता अली खुमैनी का मानना था कि यह संगठन हमेशा ईरान को अमेरिका से सुरक्षित रखेगा। बासिज में ग्रामीण इस्लामिक रूढीवादी पृष्ठभूमि के लोगों को ही शामिल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर यह संगठन मस्जिद के जरिए लोगों को नियंत्रित करता है।

बड़े पैमाने पर इस संगठन को ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड नियंत्रित करता है। इस संगठन में करीब 2 करोड़ सैनिक हैं, जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है। 2009 और 2022 के दौरान इसी बासिज नामक संगठन ने ईरान में विद्रोह को दबाया था। अब एक बार फिर से ईरान में विद्रोह दबाने का जिम्मा बासिज को मिला है।

अमेरिका ने बासिज बल और उसके कुछ कमांडरों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसे अमेरिका एक खूंखार संगठन मानता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक बासिज समूह ईरान में असहमति की लहरों को हिंसक रूप से कुचलने में अग्रणी भूमिका निभाता है।

ईरान में बवाल और उस पर एक्शन

ईरान में 27 दिसंबर 2025 से ही महंगाई को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की जो डिमांड है वो जायज है, लेकिन कुछ दंगाईयों ने पूरे प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है।

HRANA के मुताबिक ईरान में विरोध-प्रदर्शन को शांत करने के लिए 500 से ज्यादा नागरिकों की हत्या की गई है। वहीं ईरान में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में अत्याचार जारी रहता है तो हम सैनिक भेज सकते हैं।

बांग्लादेश के वायुसेना में जान फूंक रहा चीन, ढाका में बनेगी 447 करोड़ रुपए की सैन्य ड्रोन फैक्ट्री

ढाका, एजेंसी। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जुट गया है। पिछले दिनों बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए थे। देश में अशांति रही। इसी के बाद अब बांग्लादेश अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन के साथ डील करने जा रहा है। बांग्लादेश अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए चीन के साथ समझौता करने की योजना बना रहा है। इस समझौते के तहत देश में एक सैन्य ड्रोन निर्माण फैक्ट्री स्थापित की जाएगी।

बांग्लादेश चीन के साथ 608 करोड़ टका (भारत के 447 करोड़ के बराबर) का समझौता करने जा रहा है। डील पर औपचारिक हस्ताक्षर होने से पहले, 6 जनवरी को वित्त मंत्रालय ने प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट का आधिकारिक नाम है—मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) के लिए विनिर्माण संयंत्र की स्थापना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है ("Establishment of Manufacturing Plant and Transfer of Technology (ToT) for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)"।

कैसे होगा राशि का इस्तेमाल?

द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, इस 608.08 करोड़ टका की परियोजना में से 570.60 करोड़ टका लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) खोलने और ड्रोन फैक्ट्री और उसकी तकनीक को इम्पोर्ट और सेटअप करने के लिए रखा गया है। कुल राशि में से 570.60 करोड़ टका चार वित्तीय वर्षों में खर्च किया जाएगा।

इस साल: 106 करोड़ टका

FY2026-27: 155 करोड़ टका

FY2027-28: 155 करोड़ टका

FY2028-29: लगभग 154.60 करोड़ टका

बाकी 37.47 करोड़ टका स्थानीय मुद्रा में खर्च किया जाएगा, जो LC खोलने के शुल्क, VAT और SWIFT शुल्क को कवर करेगा।

क्या है प्रोजेक्ट का मकसद?

शनिवार को जब इस बारे में पूछा गया, तो वित्त सलाहकार सालेहुद्दिन अहमद ने अभी ड्रोन फैक्ट्री या फाइटर जेट्स के आयात पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ड्रोन फैक्ट्री और ToT आयात के प्रस्ताव की मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, कई चर्चाएं चल रही हैं कि फाइटर जेट्स किस देश से खरीदे जाएंगे। इसलिए फिलहाल मैं ड्रोन या फाइटर जेट्स पर बात नहीं करूंगा। पहले सब कुछ फाइनल हो जाए।

बांग्लादेश वायुसेना इस परियोजना को लागू करेगी, जिसमें तकनीक चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन (CETC) इंटरनेशनल की ओर से दी जाएगी। CETC इंटरनेशनल चीन की एक राज्य-स्वामित्व वाली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद बांग्लादेश वायुसेना को देश के अंदर ही ड्रोन का निर्माण और रखरखाव करने में सक्षम बनाना है।

यूनुस ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

वित्त मंत्रालय की मंजूरी से पहले, चीफ एडवाइजर और रक्षा मंत्रालय के प्रभारी सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है-

इस वित्तीय वर्ष का खर्च पहले से मौजूद बजट से किया जाएगा और कोई नया बजट नहीं मांगा जाएगा।

अगले वित्तीय वर्ष से लेकर FY2028-29 तक जरूरी पैसा वायुसेना के तय किए गए वार्षिक बजट में ही मैनेज किया जाएगा।

सभी भुगतान मौजूदा वित्तीय नियमों के अनुसार लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) के जरिए किए जाएंगे।

स्वीकृत पैसा सिर्फ इस प्रस्तावित अनुबंध के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

फ्लैट-विला सौंपने का वादा कर 700 खरीदारों से की 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, ऑडिट से पता चली गबन की राशि

नई दिल्ली, एजेंसी। कंपनी ने लोगों को भरोसा दिया कि उन्हें तय समय पर फ्लैट/विला मिलेगा। इस भरोसे पर लोगों ने अपना पैसा लगा दिया। लंबा समय बीत गया, लेकिन लोगों को न तो फ्लैट मिला और न ही विला। ग्राहकों को फ्लैट देने या उनकी रकम वापस करने में कंपनी पूरी तरह विफल रही। लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प लिया गया। हैदराबाद में फ्लैट/विला सौंपने का वादा किए गए 700 से अधिक घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। ईडी ने इस मामले में मेसर्स साहती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीपीएल) के पूर्व निदेशक और बिक्री एवं विपणन प्रमुख बी. लक्ष्मीनारायण और संधू पूर्णचंद्र राव के खिलाफ कार्रवाई की है। कई संपत्तियों को अटैच किया गया है।

ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा मेसर्स एसआईवीपीएल, बी. लक्ष्मीनारायण और अन्य के खिलाफ विश्व स्तरीय आवासीय गेटेड समुदाय के निर्माण के लिए 'प्री-लॉन्च ऑफर' का विज्ञापन करने और संभावित खरीदारों से भारी रकम वसूलने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर इस केस की जांच शुरू की थी। हालांकि, कंपनी ग्राहकों को फ्लैट देने या उनकी रकम वापस करने में विफल रही। इस प्रकार उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया गया। ईडी की जांच में पता चला है कि एसआईवीआईपीएल के पास आवश्यक आरईआरए/एचएमडीए की अनुमति नहीं थी। परियोजना के लिए कोई एस्क्रो खाता भी नहीं था। निवेशकों से प्राप्त धनराशि विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी। उसे नकद में भी एकत्र किया गया।

आरोपियों ने मेसर्स एसआईवीपीएल की अवैध रूप से शुरू की गई परियोजनाओं में इन्वेंट्री की बिक्री के माध्यम से 800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्र की। आवश्यक अनुमतियों/अनुमोदनों के बिना इन्वेंट्री की बिक्री के झूठे बहाने से जनता को धोखा दिया। उन्होंने खरीदारों से बड़ी मात्रा में नकद राशि एकत्र की, जिसे एसआईवीपीएल के खातों में दर्ज नहीं किया गया। इसका स्पष्ट उद्देश्य एसआईवीपीएल की धनराशि को छिपाना और उसका गबन करना था। सरवानी एलीट परियोजना में इन्वेंट्री की बिक्री के बहाने खरीदारों से 216.91 करोड़ रुपये से अधिक नकद एकत्र किए गए। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि अपराध की आय को मेसर्स सिवीपीएल के फंड को संबंधित और असंबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को फर्जी बैंकिंग लेनदेन के जरिए ट्रांसफर करके, बिना किसी वास्तविक कारोबार के, गबन किया गया था। इसके अलावा, निकासी के बाद मेसर्स सिवीपीएल के बैंक खातों से नकदी के रूप में अपराध की आय की एक बड़ी राशि का गबन किया गया। बी. लक्ष्मीनारायण और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भी अपराध की आय को विदेशों में बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। संदू पूर्णचंद्र राव भी मेसर्स सिवीपीएल से लगभग 126 करोड़ रुपये के गबन में शामिल थे, जिसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि नकद में एकत्र की गई थी।

क्या आयुष डॉक्टरों को भी पंजीकृत चिकित्सक का दर्जा? याचिका पर अदालत ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने कानून, स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों से जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह कदम एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर उठाया है। याचिका में मांग की गई है कि एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह आयुष (AYUSH) डॉक्टरों को भी कानून के तहत 'पंजीकृत चिकित्सक' का दर्जा दिया जाए।

कानून में बदलाव की मांग

याचिका में 1954 के 'ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट' की समीक्षा करने की बात कही गई है। मांग है कि आज के वैज्ञानिक विकास के हिसाब से इस कानून को अपडेट करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि आयुष डॉक्टरों को इस एक्ट की धारा दो (सीसी) के तहत 'पंजीकृत चिकित्सक' शामिल किया जाना चाहिए।

कोर्ट में दिलचस्प बातचीत

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका कानून के छात्र नितिन उपाध्याय ने दायर की है, जिनका पक्ष उनके पिता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने रखा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, ₹क्या वह आपका बेटा है?₹ वकील ने कहा, ₹हां।₹ इस पर बेंच ने टिप्पणी की, ₹हमें लगा था उसे गोल्ड मेडल वगैरह मिलेगा, लेकिन वह तो पीआईएल दाखिल कर रहा है। अब तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते?₹ कोर्ट ने आगे कहा कि वे नोटिस जारी कर रहे हैं, सिर्फ उनके बेटे के लिए, ताकि वह अच्छे से पढ़ाई करे।

विज्ञापन पर रोक से जुड़ी समस्या

इस एक्ट का मकसद कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करना है, ताकि जादुई गुणों का दावा करने वाले उपायों के कुछ खास उद्देश्यों के लिए विज्ञापन पर रोक लगाई जा सके। एक्ट की धारा दो (सीसी) 'पंजीकृत चिकित्सक' की परिभाषा से संबंधित है। याचिका में कहा गया है, ₹यह एक्ट जनता को झूठे और गुमराह करने वाले मेडिकल विज्ञापनों से बचाने के लिए बनाया गया था। हालांकि, धारा तीन (डी) कुछ बीमारियों और स्थितियों से संबंधित विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाती है।₹ वहीं एक्ट की धारा तीन कुछ बीमारियों और विकारों के इलाज के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर रोक से संबंधित है।

दलील में क्या?

याचिका में कहा गया है कि आयुष डॉक्टर कानून की धारा 14 की छूट के दायरे में नहीं आते। इस वजह से वे गंभीर बीमारियों की दवाओं का विज्ञापन नहीं कर पाते और जनता को इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। कानून की धारा तीन(डी) सच्चे और झूठे विज्ञापनों में फर्क किए बिना सब पर रोक लगाती है। दलील है कि इस पुराने कानून ने बीमारियों के इलाज की जानकारी पाने के अधिकार को खत्म कर दिया है। कानून का मकसद हानिकारक विज्ञापनों को रोकना था, लेकिन अब यह आयुष डॉक्टरों के सही विज्ञापनों को भी रोक रहा है। याचिका में कहा गया है कि वैज्ञानिक रूप से सही विज्ञापन मरीजों तक जानकारी पहुंचाने का सही जरिया हैं। इसलिए, मांग की गई है कि केंद्र सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाए। यह समिति आज के विज्ञान के हिसाब से कानून की समीक्षा करे और उसे अपडेट करे।

बजने वाली है शहनाई... रश्मिका-विजय ही नहीं, ये सितारे भी करने वाले हैं 2026 में शादी

साउथ इंडस्ट्री के लोकप्रिय कपल्स में से एक विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यह साल 2026 के फर्स्ट हाफ में शादी कर लेगा। कपल ने शादी करने के लिए लोकेशन भी फाइनल कर ली है।

प्यार की नई-नई कहानियों और पुराने रिश्तों की गूंज के बीच साल 2026 बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के लिए शादियों वाला साल बनने जा रहा है। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले कई स्टार कपल अब असल जिंदगी में हमेशा के लिए एक-दूसरे का हाथ थामने की तैयारी में हैं।

साउथ की सुपरहिट जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और फैंस इस जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं। दोनों ने अक्टूबर 2025 में पर्सनल तरीके से सगाई की थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल थे।

अब रिपोर्ट्स की मानें तो ये कपल 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के एक शाही महल में शादी के बंधन में बंधने वाला है। शादी और समारोह को भी काफी सादगी और प्राइवेसी के साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें खासतौर पर परिवार और खास दोस्त ही शामिल होंगे।

पॉपुलर एक्ट्रेस जान्हवी कपूर और बिजनेसमैन शिखर पहाड़िया लगभग 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई बार वेकेशन और फैमिली फंक्शन में साथ देखा गया है। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को पब्लिक तौर से कबूल नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जोड़ी भी 2026 में शादी कर सकती है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन भी अगले साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इन दोनों की शादी 11 जनवरी 2026 को उदयपुर में होने वाली है। हाल ही में कृति ने क्रिसमस सेलिब्रेशन तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें स्टेबिन भी मौजूद दिखे थे।

बॉलीवुड के स्टार कपल ऋतिक रोशन और सबा आजाद करीब 4 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर वेकेशन और फैमिली फंक्शन में साथ देखा जाता है और सबा रोशन फैमिली इवेंट्स का भी हिस्सा बनी हैं। खबरें हैं कि ये रोमांटिक जोड़ी 2026 में शादी करने की प्लानिंग में है।

ओ रोमियो का फर्स्ट लुक आया सामने, खूंखार अंदाज में दिखे शाहिद कपूर ; 13 फरवरी रिलीज होगी फिल्म

शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म ओ रोमियो का फर्स्ट लुक आज सामने आ गया है। इस पहले लुक में शाहिद काफी खूंखार अंदाज में नजर आ रहे हैं। लाल रंग के बैकग्राउंड में शाहिद का चेहरा खून से लथपथ दिख रहा है। वहीं वो जोश में चीखते दिख रहे हैं। पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है कि शाहिद और विशाल भारद्वाज एक बार फिर कमीने जैसा कुछ अलग लाने वाले हैं।

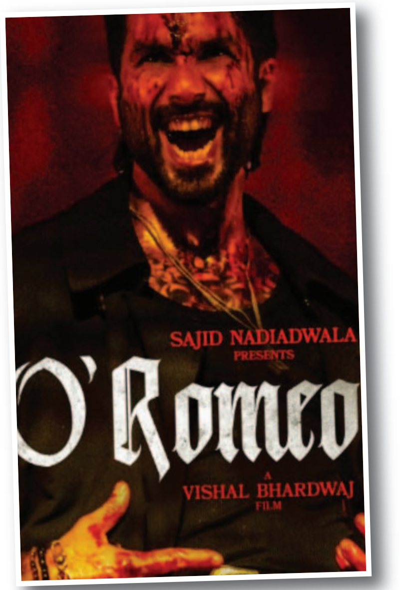

इसके साथ ही मेकर्स ने ये भी साफ कर दिया है कि फिल्म की पहली झलक या टीजर कल सामने आएगा। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी घोषित कर दी है।

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की घोषणा के बाद से ही फैंस फिल्म की झलक पाने के लिए बेकरार थे। अब शाहिद कपूर के इस पहले पोस्टर को ही देखकर फैंस उत्साहित हो गए हैं। पोस्टर में शाहिद का खूंखार अंदाज तो दिख ही रहा है, जिसमें उनके हाथ पर बना टैटू और कई ब्रेसलेट लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इस पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है कि शाहिद एक और विशाल भारद्वाज मिलकर एक बार फिर कुछ अलग और नया करने वाले हैं। ये शाहिद और विशाल की साथ में चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों कमीने, हैदर और रंगून साथ में कर चुके हैं। इनमें कमीने और हैदर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थीं और क्रिटिक्स ने भी इन्हें जमकर सराहा था। वहीं पिछली तीनों ही फिल्मों में विशाल भारद्वाज ने शाहिद को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखाया है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर विशाल, कुछ अलग अंदाज में ही शाहिद को पेश करने वाले हैं।

ओ रोमियो का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है। जबकि फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में एक दमदार स्टारकास्ट नजर आएगी, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। इस भारी भरकम स्टारकास्ट में शाहिद कपूर के अलावा नाना पाटेकर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, अरुणा ईरानी और फरीदा जलाल जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं। फिलहाल अभी तक फिल्म की कहानी के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब दर्शकों को 13 फरवरी का इंतजार है, जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com

*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com